



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-23] रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 नवम्बर, 2022 ई0 (अग्रहायण 05, 1944 शक सम्वत्) [संख्या-48

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक घन्टा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	रु0 3075
भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक भोटिस	911-916	1500
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियाँ, आज्ञाएँ, विज्ञप्तियाँ इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	853-862	1500
भाग 2-आज्ञाएँ, विज्ञप्तियाँ, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियाँ, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया	—	975
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटीयों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियाँ	—	975
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि	577-625	975
स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि	—	1425

## भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

### माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3

07 अक्टूबर, 2022 ई०

संख्या 1158/XXIV-B-3/22/16630-

प्रेषक,

रविनाथ रामन,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**विषय:-** राज्य के पांच जनपदों उत्तरकाशी, धमोली, रुद्रप्रयाग, ऊद्यमसिंहनगर एवं बागेश्वर में राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों का संचालन/निर्माण सोसायटी मोड में किये जाने के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं० 1095/XXIV-3/12/04(02)2008 दिनांक 18 सितम्बर, 2012 द्वारा राज्य के राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव आवासीय विद्यालयों व राज्य में संचालित अन्य आवासीय विद्यालयों को सोसायटी मोड में संचालित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे, तत्पश्चात् शासनादेश सं० 1171/XXIV-3/12/02(01)2011 दिनांक 24 सितम्बर, 2012 द्वारा राज्य के पांच जनपदों उत्तरकाशी, धमोली, रुद्रप्रयाग, ऊद्यमसिंहनगर एवं बागेश्वर में संचालित श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव आवासीय विद्यालयों का नाम परिवर्तित कर राजीव गांधी नवोदय विद्यालय करते हुये इन विद्यालयों का निर्माण एवं संचालन लोक निजी सहभागिता (पी०पी०पी० मोड) में किये जाने का निर्णय लिया गया था।

2- राजीव गांधी नवोदय विद्यालय उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं ऊद्यमसिंहनगर का निर्माण एवं संचालन की प्रक्रिया बाधित होने के दृष्टिगत जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उक्त रा०गां०विद्यालयों की स्थापना की जानी थी, उसे प्राप्त किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है एवं इससे उक्त विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

3- उक्त के सम्बन्ध में आपके पत्रांक: 5ख(2)/4234/रा०गां०न०वि०/2022-23 दिनांक 23 मई, 2022 पत्रांक: सेयार्ये-2/13476/आ०वि०स०(पी०पी०पी० मोड)/22/2022-23 दिनांक 22 अगस्त, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त वर्णित समस्याओं के निराकरण किये जाने हेतु सम्यक् निर्णयोपरान्त राजीव गांधी



नवोदय विद्यालय—उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, धारेश्वर एवं उद्यमसिंहनगर का निर्माण एवं संचालन पी०पी०पी० (लोक निजी सहभागिता) मोड से परिवर्तित कर सोसायटी मोड में किये जाने एवं राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, चमोली का निर्माण एवं संचालन पी०पी०पी० (लोक निजी सहभागिता) मोड से परिवर्तित कर सोसायटी मोड में किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4— प्रश्नगत रा०गा०न०विद्यालयों का वित्तीय, शैक्षिक एवं सामान्य प्रबंधन शासनादेश सं० 1095/XXIV-3/12/04(02)2008 दिनांक 18 सितम्बर, 2012 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

5— यह आदेश वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जेनरेटेड सं० 87332/2022 दिनांक 29 सितम्बर, 2022 से प्राप्त सहमति/परामर्श से निर्गत किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,  
रविनाथ रामन,  
सचिव।

### पशुपालन अनुभाग-1

#### अधिसूचना

03 नवम्बर, 2022 ई०

संख्या 1597/XV-1/22/7(13)/2022—अधिसूचना संख्या—1387/XV-1/22/7(13)2022 दिनांक 30 सितम्बर, 2022 के द्वारा Lumpy Skin Diseases (LSD) के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु संपूर्ण प्रदेश में गौ एवं महिषवंशीय पशुओं के अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं तथा अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्जनपदीय परिवहन को निरुद्ध करने सहित गौ एवं महिषवंशीय पशुओं का आवागमन, प्रदर्शनियों, गौ एवं महिषवंशीय के पशुओं एकत्रित करने वाली समस्त गतिविधियों को आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 माह के लिए निरुद्ध किया गया था। Lumpy Skin Diseases (LSD) के दृष्टिगत उक्त गतिविधियों को यह आदेश निर्गत होने की तिथि से पुनः 01 माह के लिए निरुद्ध किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

#### अधिसूचना

09 नवम्बर, 2022 ई०

संख्या 1604/XV-1/07(29) 2017—भारवाहक एवं कर्षक पशुओं के प्रति अनावश्यक क्रूरता के निवारण के उद्देश्य से एतद्वारा श्री राज्यपाल, *The Prevention of Cruelty to (Licensing of Farriers) Rules, 1965* के Rule-1(b) के प्राविधानानुरूप, *The Prevention of Cruelty (Licensing of Farriers) Rules, 1965* को उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से लागू किये जाने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

प्रत्येक जनपद के "मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी" को *The Prevention of Cruelty to (Licensing of Farriers) Rules, 1965* के Rule-2(d) के तहत Licensing Authority घोषित किया जाता है।

अधिसूचना

09 नवम्बर, 2022 ई0

संख्या 1605/XV-1/22(07)/2017-भारवाहक एवं कर्षक पशुओं के प्रति अनावश्यक क्रूरता के निवारण तथा इन पशुओं को अत्यधिक शोषण से बचाये जाने के उद्देश्य से एतद्वारा श्री राज्यपाल, *The Prevention of Cruelty to Draught & Pack Animals Rules, 1965* के Rule-1(2) के प्राविधानानुरूप, *The Prevention of Cruelty to Draught & Pack Animals Rules, 1965* को उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत लागू किये जाने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह अधिसूचना इस प्रतिबन्ध एवं शर्त के साथ तत्काल प्रभाव से लागू होगी कि, इस संबंध में नविष्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका *SPECIAL LEAVE PETITION (CIVIL) Diary No(s). 43990/2019 (THE STATE OF UTTARAKHAND & ORS. VERSUS NARAYAN DUTT BHATT & ORS.)* में निर्यत होने वाले आदेशों के अधीन रहेगी।

आज्ञा से,

डा0 बी0वी0आर0सी0पुरुषोत्तम,  
सचिव।

वित्त अनुभाग-9अधिसूचना

06 सितम्बर, 2022 ई0

संख्या 400/2022/XXVII(9)/स्टाम्प-02/2010-श्री राज्यपाल, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908, (अधिनियम संख्या 16, सन् 1908) की धारा 5 संपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, 1897) की धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके इस निमित्त जारी की गयी अधिसूचना संख्या 01/XXVII(9)-2010/स्टाम्प-02/2010 दिनांक 08 मार्च, 2010 तथा अधिसूचना संख्या-एस0आर0-1057/वस-312(273)/70 दिनांक 23 अप्रैल, 1980 में आंशिक उपान्तर करके उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-348(1)/2018/XXVII(8)-2010/स्टाम्प-11/2014, दिनांक 11 दिसम्बर, 2018 द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 5 के अधीन राज्य के अधीन समस्त उपजिलों की सीमाओं को यथावत रखते हुये जिले में अवस्थित समस्त उपजिलों का क्षेत्राधिकार समवर्ती किये जाने तथा इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या-413/2019 नरपाल सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 27 जून, 2019 को पारित स्थगनादेश एवं प्रकरण में अन्तिम निर्णय के अधीन उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-248/XXVII(II)-2020-02(24)/2008 टी0सी0 दिनांक 12 मई, 2020 द्वारा 19 राजस्व ग्रामों को तहसील जसपुर की न्याय पंचायत "भरतपुर" से पृथक कर तहसील काशीपुर में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से विलेखों के पंजीकरण हेतु जिला ऊधमसिंहनगर के उपजिला काशीपुर एवं उपजिला जसपुर की सीमाओं को निम्नानुसार जैसा कि नीचे अनुसूची स्तम्भ-3 में प्रत्येक के सामने दर्शाया गया है, विहित करते हैं :-

अनुसूची :

क्र0 सं0	उपजिले का नाम	उपजिले की सीमायें
1.	काशीपुर	अधिसूचना संख्या 01/XXVII(9)-2010/स्टाम्प-02/2010 दिनांक 08 मार्च, 2010 के क्रम में निर्धारित सीमाओं के साथ उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-248/XXVII(II)-2020-02(24)/2008 टी0सी0 दिनांक 12 मई, 2020 द्वारा तहसील काशीपुर में सम्मिलित न्याय पंचायत "भरतपुर" के नाम 19 ग्राम



2.	जसपुर	अधिसूचना संख्या 01/XXVII(9)-2010/स्टाम्प-02/2010 दिनांक 08 मार्च, 2010 के कम में निर्धारित सीमाओं में से उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-248/XVII(II)-2020-02(24)/2008 टी०सी० दिनांक 12 मई, 2020 द्वारा तहसील जसपुर से पृथक्कृत न्याय पंचायत "भरतपुर" के नाम 19 ग्राम को छोड़कर जसपुर की राजस्व तहसील का सम्पूर्ण क्षेत्र
----	-------	--

आज्ञा से,

देवेन्द्र पालीवाल,

अपर सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.400/XXVII(9)/Stamp-02/2010 Dehradun, dated, 06 September, 2022 for general information.

**NOTIFICATION**

September 06, 2022

**No.400/2022/XXVII(9)/Stamp-02/2010**—In exercise of the powers conferred under section-5 of Registration Act, 1908, (Act No. 16 of 1908) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 16 of 1897) and in partial modification of Notification no. 01/XXVII(9)-2010/stamp-02/2010 dated 08<sup>th</sup> March 2010 and Notification no. SR-1057/10-312(273)/70 dated 23<sup>rd</sup> April, 1980 in the context of Notification no.-248/XVII(II)/2020-02(24)/2008 T.C dated 12<sup>th</sup> May, 2020 of the Uttarakhand Government which separated 19 revenue villages of Nyay panchayat "Bharatpur" of Tehsil Jaspur and included them in Tehsil Kashipur, under the Notification no. 348(1)2018/XXVII(9)/Stamp-11/2014 dated 11.12.2018 of Uttarakhand Government under section 5 of Registration Act 1908, keeping the limits of all sub district in the state unchanged, makes the jurisdiction of all sub district in the district concurrent and under the stay & final Judgement of Hon'ble High Court, Uttarakhand Nainital in writ petition no-413/2019 Narpal singh v/s State of Uttarakhand and others in this regard, the Governor is pleased to define the limits of sub district Kashipur and sub district Jaspur for the purpose of registration of documents with effect from the date of publication of this notification as mentioned in column-3 of the schedule given below.

**SCHEDULE**

Sl. No.	Sub-Districts of Udhamasinghnagar	Limits of Sub-District's
1.	Kashipur	Limits as assigned by Notification no. 01/XXVII(9)-2010/stamp-02/2010 dated 08 <sup>th</sup> March 2010 along with 19 villages of Nyay panchayat "Bharatpur" included in Tehsil Kashipur by notification no-248/ XVII(II)/ 2020 - 02(24)/2008 T.C dated 12 <sup>th</sup> May, 2020
2.	Jaspur	Limits as assigned by Notification no. 01/XXVII(9)-2010/stamp-02/2010 dated 08 <sup>th</sup> March 2010 excluding 19 villages of Nyay panchayat "Bharatpur" separated from Tehsil Jaspur by notification no-248/ XVII(II)/2020-02(24)/2008 T.C dated 12 <sup>th</sup> May, 2020, all areas of Revenue teshil Jaspur.

By Order,

DEVENDRA PALIWAL,

Add. Secretary.

## वित्त अनुभाग-8

19 अक्टूबर, 2022 ई०

संख्या 71352/2022/12(B)(100)/XXVII(8)/2014-

प्रेषक,

देवेन्द्र पालीवाल,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त राज्य कर,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:—श्रीमती शिवानी त्रिपाठी, सहायक आयुक्त राज्य कर, का नाम परिवर्तित किये जाने की शासकीय अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रकरण में अपर आयुक्त(वि०वे०) राज्य कर मुख्यालय, देहरादून के पत्र सं०-2261/ आयु०रा०कर०उत्तरा०/स्था०अनु०/2022-23/देहरादून, दिनांक 15.07.2022 एवं संगत अभिलेखों/संलग्नकों के परीक्षणोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रीमती शिवानी त्रिपाठी, सहायक आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड का नाम विवाह उपरांत परिवर्तित कर "श्रीमती शिवानी त्रिपाठी भारती" किये जाने की शासकीय अनुमति संगत शासनादेश में निहित प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है—

- (1) नाम परिवर्तन से सम्बन्धित सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय।
- (2) नाम परिवर्तन किये जाने सम्बन्धी समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए अग्रोत्तर कार्यवाही सम्पन्न की जाय।
- (3) यह सुनिश्चित किया जाय कि नाम परिवर्तन किये जाने से कोई न्यायिक प्रक्रिया बाधित न हो।

देवेन्द्र पालीवाल,  
अपर सचिव।



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 नवम्बर, 2022 ई0 (अग्रहायण 05, 1944 शक सम्बत)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आझाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND NAINITAL

NOTIFICATION

November 03, 2022

No. 336/XIV/57/Admin.A/2003--Shri Ajay Chaudhary, 1<sup>st</sup> Additional District & Sessions Judge, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 12.09.2022 to 24.09.2022 with permission to prefix 10.09.2022 & 11.09.2022 as second Saturday & Sunday holidays and suffix 25.09.2022 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

November 03, 2022

No. 337/XIV-35/Admin.A/2008--Shri Ramesh Singh, Chief Judicial Magistrate, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 10.10.2022 to 21.10.2022 with permission to prefix 08.10.2022 & 09.10.2022 as second Saturday and Sunday holidays and suffix 22.10.2022 to 26.10.2022 as Diwali holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection),



**THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL****NOTIFICATION***November 03, 2022*

No. 338/UHC/Admin.A/2022--

**THE UTTARAKHAND HIGH COURT ELECTRONIC TRUE COPY RULES, 2022**

In exercise of the powers conferred under Articles 225 and 227 of the Constitution of India and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Uttarakhand hereby makes, with the approval of the Governor of the State of Uttarakhand, the following Rules for obtaining online certified copy of judgments and orders of the High Court of Uttarakhand as well as the courts subordinate thereto:

**1. Short Title, Applicability and Commencement:**

- 1.1 These Rules shall be called the Uttarakhand High Court Electronic True Copy Rules, 2022.
- 1.2 These Rules shall come into force with immediate effect.
- 1.3 These rules shall apply for on-line certified true copy of the Judgments and Orders, passed in any proceeding, whether pending or decided, in the High Court of Uttarakhand, Nainital and all the District Courts subordinate to it.
- 1.4 These Rules shall amend to the extent of conflict, and consolidate the existing Rules and Practice Directions, including those prescribed in (1) the Allahabad High Court Rules 1952 (Rules of Court 1952), and other Rules governing the Procedure of the High Court, (2) General Rules (Civil) 1957, and the corresponding Circulars/Orders of the High Court of Uttarakhand, and, (3) General Rules (Criminal) 1977, and the corresponding Circulars/Orders of the High Court of Uttarakhand.

**2. Definitions:**

- 2.1 "BAR Code" means a small image of lines (bars) and spaces used for representing data in a visual, machine-readable form.
- 2.2 "Court" shall mean either the High Court or a District Court.
- 2.3 "District Court" means a Court subordinate to the High Court of Uttarakhand.
- 2.4 "Electronic True Copy" or "eTrue copy" means a copy of any Judgment or Order of the Court issued under these Rules.
- 2.5 "High Court" means the High Court of Uttarakhand, Nainital.
- 2.6 "QR Code" means Quick Response Code.

**3. Any person can apply for eTrue copy:**

- 3.1 An eTrue Copy can be obtained by any person.



**4. Steps in generating an eTrue copy:**

- 4.1 An eTrue Copy of a Judgment or Order of the Court can be obtained from link to the eTrue Copy module available on the official website or the official smartphone app of the High Court, or the District Court, as the case may be.
- 4.2 A person desirous of obtaining an eTrue Copy of a Judgment or Order shall provide following details on the eTrue Copy module;

- a. Name
- b. Mobile Number
- c. E-mail, if any
- d. Details of the Applicant.

- 4.3 An eTrue copy of the particular order/judgment may also be shared on the e-mail, if it is provided by the applicant.

**5. Contents of the eTrue copy:**

- 5.1 Every eTrue copy generated through the process as mentioned in Rule 4 shall consist of a memo page along with the copy of judgment/order.
- 5.2 The memo page shall consist of a 20 digit Bar Code, a Special Code below the 20 digit Bar Code, QR Code and a Seal of the "Court" with date of issue for the purpose of future authentication from National Judicial Data Grid Database.
- 5.3 Every page of the judgment/order generated as eTrue copy shall contain a QR Code by means of which the contents and authenticity of the judgment/order can be verified from the National Judicial Data Grid (NJDG) portal.
- 5.4 The memo page and each page of eTrue copy shall bear the following statement:  
"True copy of the Judgment/Order. It is issued under the Uttarakhand High Court Electronic True Copy Rules, 2022 to ....."

**6. Legal effect of eTrue copy:**

- 6.1 An eTrue Copy shall be deemed to be a certified copy for all purposes including judicial work, unless the context otherwise requires.

By Order of the Court,  
Sd/-

VIVEK BHARTI SHARMA,

Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND NAINITALNOTIFICATION

November 05, 2022

No. 339/XIV-a-47/Admin.A/2020--Ms. Akmal, Judicial Magistrate, Bageshwar is hereby sanctioned maternity leave of 180 days w.e.f. 02.05.2022 to 28.10.2022.

NOTIFICATION

November 05, 2022

No. 340/XIV-a-41/Admin.A/2013--Shri Manoj Garbyal, 2<sup>nd</sup> Additional District & Sessions Judge, Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 04 days w.e.f. 17.10.2022 to 20.10.2022.

NOTIFICATION

November 05, 2022

No. 341/XIV-a/59/Admin.A/2012--Ms. Payal Singh, Civil Judge (Sr. Div.), Kashipur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 10 days w.e.f. 10.10.2022 to 19.10.2022.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITALNOTIFICATION

November 05, 2022

No. 342/UHC/Admin.A/2022--In exercise of the powers conferred by Article 225 of the Constitution of India and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Uttarakhand has been pleased to make following amendments in Rules of the Court, 1952 to recognize Communication received through FASTER System as per directions of Hon'ble Supreme Court of India, in Suo Moto Writ Petition (C) No.4/2021, IN RE: DELAY IN RELEASE OF CONVICTS AFTER GRANT OF BAIL:-

"Amendments in Rules of the Court, 1952"**I. Sub-rule-(3) is inserted in Rule-43 of Chapter XVIII -**

(3) e-Authenticated copies of the Interim Orders, Stay Orders, Bail Orders and Record of Proceedings of the Supreme Court of India and High Court of Uttarakhand, communicated to the duty holders through the FASTER (Fast and Secure Transmission of Electronic Records) System via secured email domain i.e., xxxx@jn.nic.in, shall be recognized for due compliance and execution by all the duty holders.



**II. Rule- 44A is inserted after Rule-44 of Chapter XVIII -****44A- e-Authenticated copies of Interim Orders, Stay Orders, Bail Orders and Record of Proceedings received through FASTER System-**

- (1) District Judge shall be responsible to receive, acknowledge the receipt and to send compliance report, of the orders of the Hon'ble Supreme Court and the High Court of Uttarakhand, sent through the FASTER system via secured email domain i.e., xxxx@jcn.nic.in.
- (2) The District Judge, on being communicated of an e-Authenticated copy of Interim Order, Stay Order, Bail Order and Record of Proceedings through the FASTER System, shall, also forward such e-Authenticated copy to the concerned Court for due compliance/execution without delay.

These amendments shall come into force with immediate effect.

**NOTIFICATION**

November 05, 2022

**No. 343/UHC/Admin.A/2022--**In exercise of powers conferred by Article 227 (2) of the Constitution of India, the High Court of Uttarakhand, Nainital, with the approval of the Governor of Uttarakhand is pleased to make the following amendments in General Rules (Criminal), 1977 and General Rules (Civil) 1957 (applicable to Uttarakhand under O.P. Reorganization Act 2000)

**"Amendment in General Rules (Criminal), 1977"****I. Rule 99-A is inserted after Rule-99 :****99-A: Duty of District Judge and Trial Court on receiving e-Authenticated copy through the FASTER SYSTEM**

- (1) e-Authenticated copies of Interim Orders, Stay Orders, Bail Orders and Record of Proceedings of the Supreme Court of India, and the High Court of Uttarakhand communicated to the duty holders through the FASTER (Fast And Secure Transmission of Electronic Records) System via the secured e-mail domain i.e. xxxx@jcn.nic.in , shall be recognized for due compliance and execution, without delay
- (2) As soon as an e-Authenticated copy of an Interim Order , Stay Order, Bail Order or Record of Proceedings of the Supreme Court of India, or the High Court of Uttarakhand is communicated to the District Judge through the FASTER SYSTEM via

secured e-mail domain, i.e. xxxx@jcn.nic.in the latter shall be responsible to receive acknowledge the receipt and to send compliance report of such order or Record of Proceeding to the Hon'ble Supreme Court or the High Court of Uttarakhand, as the case may be.

- (3) The District Judge, where such order or Record of Proceeding, relates to any other Court in the District, other than her/his own Court, shall also forward such e-Authenticated copy received through the FASTER SYSTEM to such other Court.

## **II. Amendment in Rule 102**

Present Rule 102 is renumbered as 102 (1) and a new Sub-rule (2) is inserted as follows:

- (2) The communication of e-Authenticated copies of Interim Order, Stay Order, Bail Order or Record of Proceedings, through the FASTER (Fast and Secure Transmission of Electronic Records) System shall be recognized immediately for due compliance and execution by all the duty holders, without delay.

### **"Amendment in General Rules (Civil), 1957"**

#### **I. Rule 100-A is inserted after Rule 100 as follows:**

**100A: Duty of District Judge and Trial Court on receiving e-Authenticated copy through the FASTER SYSTEM**

- (1) e-Authenticated copies of Interim Orders, Stay Orders, and Record of Proceedings of the Supreme Court of India and the High Court of Uttarakhand communicated to the duty holders through the FASTER (Fast And Secure Transmission of Electronic Records) System via the secured e-mail domain i.e. xxxx@jcn.nic.in, shall be recognized for due compliance and execution without delay.
- (2) As soon as an e-Authenticated copy of an Interim Order, Stay Order, or Record of Proceedings of the Supreme Court of India or the High Court of Uttarakhand is communicated to the District Judge through the FASTER SYSTEM via secured e-mail domain, i.e. xxxx@jcn.nic.in, the latter shall be responsible to receive, acknowledge the receipt and to send compliance report of such order or Record of Proceeding to the Hon'ble Supreme Court or the High Court of Uttarakhand, as the case may be



- (3) The District Judge, where such order or Record of Proceeding, relates to any other Court in the District, other than her/his own Court, shall also forward such a Authenticated copy received through the FASTER SYSTEM, to such other Court for compliance/execution

These amendments shall come into force with immediate effect.

By Order of the Court,

Sd/-

VIVEK BHARTI SHARMA,

Registrar General

**कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,  
टनकपुर (चम्पावत)  
आदेश**

29 सितम्बर, 2022 ई०

पत्रांक:-2852/पंजीयन निरस्त/2022-23-वाहन संख्या UK03CA1290 (HGV) मॉडल 2010 चैविस MAT373.4591P31982 इंजन न० 697TCS6PZ121696 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री केशव वत्त पन्त पुत्र श्री प्रेम बल्लम पन्त निवासी-पिथौरागढ़ रोड, ककराली गेट आमबाग, टनकपुर, जिला-चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 18/09/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैविस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.09.2022 को वाहन संख्या UK03CA1290 (HGV) मॉडल 2010 चैविस MAT373.4591P31982 इंजन न० 697TCS6PZ121696 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

**आदेश**

29 सितम्बर, 2022 ई०

पत्रांक:-2853/पंजीयन निरस्त/2022-23-वाहन संख्या URN-9021 (HGV) मॉडल 1990 चैविस VPI7917E इंजन न० 09033SVF इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री विनोद शारदा पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार शारदा निवासी गणेश ऑटोमोबाइल, टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 23/09/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैविस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.09.2022 को वाहन संख्या URN-9021 (HGV) मॉडल 1990 चैविस VPI7917E इंजन न० 09033SVF को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

29 सितम्बर, 2022 ई०

पत्रांक: 2654/पंजीयन निरस्त/2022-23-वाहन संख्या UGP 4837 (HGV) मॉडल 1990 चैचिस 76VFJ11394 इंजन न० B15301SVF इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री नरेन्द्र कृष्ण शारदा पुत्र श्री सुरेन्द्र कृष्ण शारदा निवासी-सिमेण्ट रोड, टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 23/09/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.09.2022 को वाहन संख्या LGP 4837 (HGV) मॉडल 1990 चैचिस 76VFJ11394 इंजन न० B15301SVF को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

29 सितम्बर, 2022 ई०

पत्रांक:-2657/पंजीयन निरस्त/2022-23-वाहन संख्या UK03CA1543 (HGV) मॉडल 2008 चैचिस 373145ARZ100989 इंजन न० 697TC56ARZ100544 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री हयाम सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह निवासी-ग्राम कुटरी, चक्रपुर, जटौमा, उधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। दिनांक 18/09/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.09.2022 को वाहन संख्या UK03CA1543 (HGV) मॉडल 2008 चैचिस 373145ARZ100989 इंजन न० 697TC56ARZ100544 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

30 सितम्बर, 2022 ई०

पत्रांक:-2663/पंजीयन निरस्त/2022-23-वाहन संख्या LA104839 (HGV) मॉडल 2008 चैचिस 373135GTZ733887 इंजन न० 697TC56FTZ129772 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री देवेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री फतेह सिंह रावत निवासी-विष्णुपुरी कालोनी, पोस्ट-टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 23/09/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.09.2022 को वाहन संख्या UA104839 (HGV) मॉडल 2008 चैचिस 373135GTZ733887 इंजन न० 697TC56FTZ129772 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।



आदेश

30 सितम्बर, 2022 ई0

पत्रांक: 2664/पंजीयन निरस्त/2022-23 वाहन संख्या UA04E1740 (MAXI CAB) मॉडल 2007 चैचिस MA1MB2GFK73B40593 इंजन न0 GF74A55900 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन मो0 मोहसिन पुत्र स्व0 सुलेमान निवासी-मनिहारगोट, टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 14/09/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.09.2022 को वाहन संख्या LA04E1740 (MAXI CAB) मॉडल 2007 चैचिस MA1MB2GFK73B40593 इंजन न0 GF74A55900 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

30 सितम्बर, 2022 ई0

पत्रांक:-2665/पंजीयन निरस्त/2022-23-वाहन संख्या UK03CA1456 (HGV) मॉडल 2008 चैचिस 373145JSZ132575 इंजन न0 697TC56JSZ142698 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री ललित मोहन जोशी पुत्र श्री बंशीधर जोशी निवासी-मकान संख्या 23(5) वार्ड नम्बर 03 हॉस्पिटल रोड शारदा चुंगी टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 23/09/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.09.2022 को वाहन संख्या UK03CA1456 (HGV) मॉडल 2008 चैचिस 373145JSZ132575 इंजन न0 697TC56JSZ142698 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

30 सितम्बर, 2022 ई0

पत्रांक:-2667/पंजीयन निरस्त/2022-23-वाहन संख्या UTF 7848 (HGV) मॉडल 1997 चैचिस VPJ1923C इंजन न0 10.1341138 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री विकास सिंह पुत्र श्री केशव सिंह निवासी-नायकगोट टनकपुर, जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 16/09/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.09.2022 को वाहन संख्या UTF 7848 (HGV) मॉडल 1997 चैचिस VPJ1923C इंजन न0 011341.38 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

30 सितम्बर, 2022 ई०

पत्रांक:-2668/पंजीयन निरस्त/2022-23 वाहन संख्या UP291253 (HGV) मॉडल 2000 चैचिस 46337 इंजन न० B52705SVF इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री हरीश चन्द्र पुत्र श्री जमुना प्रसाद निवासी श्रीपुर विचवा खटीमा जिला उधम सिंह नगर के नाम पंजीकृत है। दिनांक 14/09/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (बम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 65(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.09.2022 को वाहन संख्या UP291253 (HGV) मॉडल 2000 चैचिस 46337 इंजन न० B52705SVF को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

30 सितम्बर, 2022 ई०

पत्रांक:-2669/पंजीयन निरस्त/2022-23-वाहन संख्या UA034669 (HGV) मॉडल 2006 चैचिस VFJ35236P इंजन न० B4 177SVF इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री सुन्दर सिंह कुल्याल पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह कुल्याल निवासी-ग्राम-दुधौरी, पोस्ट-अमोड़ी जिला बम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 21/09/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (बम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 65(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.09.2022 को वाहन संख्या UA034669 (HGV) मॉडल 2006 चैचिस VFJ35236P इंजन न० B41177SVF को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

सुरेन्द्र कुमार,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

टनकपुर (बम्पावत)





# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 नवम्बर, 2022 ई0 (अग्रहायण 05, 1944 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

## सूचना

मैंने अपना नाम सुबोध कुमार से बदलकर सुबोध कुमार गुप्ता कर लिया है, भविष्य में मुझे सुबोध कुमार गुप्ता पुत्र श्री गंगा राम गुप्ता के नाम से जाना पहचाना मुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी हैं।

सुबोध कुमार गुप्ता पुत्र श्री

गंगाराम गुप्ता निवासी 161

ए, टाईप 3, सैक्टर-3,

रानीपुर रेंज हरिद्वार।

सूचना

IT is to inform to the general public that I Shabistan Parveen Siddiqui in CBSE Board High School Marksheet and Certificate my name Shabistan Praveen Siddiqui in place of Shabistan Parveen Siddiqui which is incorrect. My correct name is Shabistan Parveen Siddiqui, D/o Mohd Ikram Siddiqui Add- H.No. 95, Van Vihar Colony Mehunwala mafi Dehradun

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Shabistan Parveen Siddiqui

D/o Mohd Ikram Siddiqui

Add- H.No. 95, Van Vihar Colony

Mehunwala mafi Dehradun

सूचना

It is to inform to the general public that I Saba Parveen Siddiqui, in CBSE Board High School Marksheet and Certificate my name Saba Praveen in place of Saba Parveen Siddiqui which is incorrect. My correct name is Saba Parveen Siddiqui, D/o Mohd Ikram Siddiqui Add- H.No. 95, Van Vihar Colony Mehunwala mafi Dehradun

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Saba Parveen S.ddiqui,

D/o Mohd Ikram Siddiqui

Add- H.No. 95, Van Vihar Colony

Mehunwala mafi Dehradun

## कार्यालय नगर पालिका परिषद लोहाघाट, चम्पावत

सार्वजनिक सूचना

12 दिसम्बर, 2017 ई०

पत्रांक 628/यूजर चार्ज उपविधि/2017 18 नगर पालिका परिषद लोहाघाट सीमान्तगत च० प्र० नगर पालिका अधिनियम 1918 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 288 की उपधारा 2 खण्ड (अ) का (घ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2011 के क्रियान्वयन हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व यूजर चार्ज उपविधि, 2017 बनायी जाती है।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व यूजर चार्ज उपविधि, 2017संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भ -

- 1 यह उपविधि नगर पालिका परिषद लोहाघाट जनपद चम्पावत की "नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व यूजर चार्ज उपविधि 2017 कहलायेगी।
- 2 यह उपविधि नगर पालिका परिषद लोहाघाट जनपद चम्पावत के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी होगी।
- 3 यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

परिभाषाएं :-

- i) नगरीय ठोस अपशिष्ट के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपधरित जैव चिकित्सीय उपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।
- ii) उपविधि से अभिप्रेत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1996 के उपबन्धों के अधीन गठित उपविधि से है।
- iii) नगर पालिका से अभिप्रेत संविधान के अनुच्छेद 243 (ध) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के संगठित नगर पालिका परिषद लोहाघाट, चम्पावत से है।
- iv) अधिशासी अधिकारी से अभिप्रेत उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1996 के अन्तर्गत पालिका केंद्रीयत सेवा नियमावली 1966 के अधीन नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है।
- v) सफाई निरीक्षक से अभिप्रेत नगर पालिका परिषद लोहाघाट चम्पावत में शासन द्वारा तैनात सफाई कर्मचारी निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगर पालिका के उस अधिकारी/कर्मचारी से है, जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन नगर पालिका परिषद बोर्ड या जिन्हें समय-समय पर अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया है।
- vi) निरीक्षक अधिकारी का अभिप्रेत अधिशासी अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से है, जिन्हें समय-समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश से निरीक्षक के लिए अधिकृत किया गया है।
- vii) 'नियम' से अभिप्रेत भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं० 648 नई दिल्ली मंगलवार 03 अक्टूबर 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली दिनांक 25 सितम्बर 2000 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम 2000 बनाये गये हैं।
- viii) अधिनियम से अभिप्रेत उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1996 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) से है।
- ix) जीव नाशित/जैव निम्नकारणीय/जैविक अपशिष्ट (biodegradable waste) से अभिप्रेत ऐसे अपशिष्ट पदार्थों से है सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है, जैसे बचा आ खाना, सब्जी एवं फल के छिलके, फूलों पौधों आदि के पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ट आदि।



- k) जीव अनाशित अपशिष्ट (non biodegradable waste) का अभिप्रेत ऐसे कूड़े-कचरा सामग्री से है, जो जीव नाशित कूड़ा कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी है ।
- xi) पुनचक्रणीय अपशिष्ट (recyclable waste) से अभिप्रेत ऐसे अपशिष्ट से है जो दोबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा विधि से परिवर्तित करके उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है जैसे- प्लास्टिक, पालीथीन (निर्धारित माइक्रोन के अन्दर ) कागज धातु, रेशम आदि ।
- xii) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (biomedical waste) से तात्पर्य ऐसी अपशिष्ट से है, जिसका जनन मानवों व पशुओं के रोग निदान, उपचार प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उससे सम्बंधित किसी अनुसंधान, क्रियाकलापों या जैविक उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो ।
- xiii) 'संग्रहण' (collection) से अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल संग्रहण, बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है।
- xiv) 'कचरा खाद बनाने' (composting) एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया से अभिप्रेत है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैविक निम्नकरण अन्तर्बलित है
- xv) 'ढहान तथा निर्माण सम्बन्ध अपशिष्ट' (demolition and construction waste) से अभिप्रेत सन्निर्माण पुर्ननिर्माण सम्बन्धित और ढहाने सम्बन्धी सक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री रोडियो और नलबे से अद्भूत अपशिष्ट से है ।
- xvi) 'व्ययन' (disposal) से भूजल सतही जल का तथा परिवेशी वायु गुणता को संतुषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है ।
- xvii) भूमिकरण (landfilling) से भूजल सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ के साथ उड़ने वाली धूल हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा बंदू आग के खतरों, पक्षियों का खतरा नशी जीव /कृत्तक, धीन हाउस गैस उत्सर्जन क्षाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षणात्मक उपक्रमों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमि भरण पर निपटान अभिप्रेत है ।
- xviii) निष्कासितक (leachate) से वह द्रव्य अभिप्रेत है जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसमें इसमें से धुलित अथवा निलंबित पदार्थ का निष्कर्ष किया है
- xix) नगर पालिका प्राधिकरण (municipal authority) में म्युनिसिपल कारपोरेशन म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र समिति (एनएसी), अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहां नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन और हथालन ऐसे किसी अधिकरण को शोषा जाता है
- xx) स्थानीय प्राधिकरण (local authority) का अभिप्रेत तत्समय प्रवर्तन किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, नगर पालिका परिषद नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत है ।
- xxi) नगरीय ठोस अपशिष्ट (municipal solid waste, के अन्तर्गत औद्योगिक परिसरमय (hazardous) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपघरित जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्ध ठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है ।
- xxii) सुविधा के परिचालक (operator of facility) से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, प्रथकरण भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अधिकरण आता है जो अपने अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन एवं हथालन के लिए नगर पालिका प्राधिकरण द्वारा इस रूप से नियुक्त किया गया है प्रसंस्करण से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये पुनर् चक्रित उत्पादों से परिवर्तन किया जाता है ।

- xxiii) पुनर्चक्र (recycling) से बहकिया अभिप्रेत है जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रथमकरण सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता है जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है ।
- xxiv) प्रथमकरण (segregation) से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनः चक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों को अलग-अलग करना अभिप्रेत है ।
- xxv) भण्डारण (storage) से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बा बंद किया जाना अभिप्रेत है जिससे कूड़ा-करकट, रोग वाहकों को आकर्षित करने, आधारा पशुओं तथा अत्यधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके ।
- xxvi) परिवहन (transportation) से विशेष रूप से डिजाइन की गयी परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा-करकट बिखरने, रोग वाहकों को पहुँच से रोका जा सके ।
- 4 कोई भी व्यक्ति /स्थापन (establishment) नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली सड़क, गली कुदपाथ किसी भी खुले स्थान पर जो नगर पालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है न डालेगा और डलवायेगा ।
- 5 नगरीय ठोस अपशिष्ट के उत्पादन व्यक्ति /स्थापन अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा, जिसमें से एक जीव निम्नकरणीय अपशिष्ट था दूसरे में पुनः चक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा ।
- 6 नगरीय ठोस अपशिष्ट के उत्पाद व्यक्ति / स्थापन द्वारा उक्त बिंदु 6 के अनुसार संग्रहित जीव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनः चक्रणीय सप्ताह में एक दिन नगर पालिका के द्वारा निर्धारित समय के अनुसार नगर पालिका के कर्मचारी /सुविधा प्रचालक (operator of a facility) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा जीव अनाशित थोले में रखकर नहीं डाला जायेगा) जिसके लिए अनुसूचि में निर्धारित दर जो समय-समय पर सशोधित की जा सकेंगी के अनुसार उत्पादक व्यक्ति /स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क (user charges) लिए जायेंगे ।
- 7 नगरीय ठोस अपशिष्ट के उत्पादन व्यक्ति /स्थापन उद्घाटन तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगर पालिका से संपर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (user charges ) देना होगा
- 8 नगरीय ठोस अपशिष्ट के उत्पादन के व्यक्ति /स्थापन द्वारा जहाँ तक संभव हो बागवानी व सभी पेड़-पौधों के कूड़ा परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा जहाँ ऐसा करना होगा जहाँ ऐसा करना संभव न हो तो नगर पालिका से संपर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (user charges ) भुगतान करना होगा किसी भी दश में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा ।
- 9 नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन व्यक्ति /स्थापन द्वारा परिसंकटमय (hazardous) अपशिष्टों के अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वारद्वार (door to door) संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा प्रचालक को देना होगा ।
- 10 नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन व्यक्ति /स्थापन जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबंधन जीव -चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हस्तन) नियम 1998 के अनुसार करेगा बिना उपचारित जीव चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा
- 11 नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला /हथालन करने वाला व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्ट को नहीं जलायेगा और न ही जलवायेगा ।
- 12 नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, प्रथमकरण संग्रहण भण्डारण, परिवहन तथा व्यनन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार निरीक्षण अधिकारी को होगा ।

13. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी जाती है तो मासिक यूजर चार्ज के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है को अपशिष्ट उत्पादन के द्वारा अथवा नगर पंचायत / सुविधा प्रदाताक तत्काल उठवाया जा सकेगा और इसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्ज वसूल किया जा सकेगा जिसकी रसीद अपशिष्ट उत्पादन को दी जायेगी वह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में नगर पंचायत / सुविधा प्रदाताक के खाते में जमा की जायेगी ।
14. अनुसूची में दी गयी दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना रु० 5.00 (पांच) के पूर्णांक में की जायेगी ।
15. उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्ज/सेवा शुल्क में छूट का प्राविधान नहीं होगा ।
16. यह कि उपविधि में दिये गये किसी नियम का उल्लंघन करने पर यदि कोई व्यक्ति या परिवार जैविक अजैविक कूड़े को सड़क व नाली में फेकता है, तो प्रथम बार रु० 200.00 दूसरी बार रु० 500.00 एवं तीसरी बार रु० 1000.00 अर्धदंड (penalty) देना होगा।
17. यह कि यदि कोई व्यक्ति आवासीय एवं व्यवसायी भवन निर्माण हेतु निर्माण सामग्री 24 घंटे के अन्दर सार्वजनिक सड़क या नाली के ऊपर से नहीं हटाता है तो प्रथम बार रु० 500.00 दूसरी बार रु० 1000.00 एवं तीसरी बार रु० 1500.00 अर्धदंड (penalty) देना होगा ।
18. यह कि नगरीय ठोस प्रबंधन के अन्तर्गत सेवा शुल्क (user charges) की दर निम्नवत हैं ।

अनुसूचित -1 सेवा शुल्क (user charges) की दरें .

क्रम सं०	अपशिष्ट उत्पादन की श्रेणी ,अपशिष्ट के प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (यूजर चार्ज) की प्रस्तावित राशि रु० में
1	आवासीय भवन	20/- प्रतिमाह
2	सब्जी एवं फल विक्रेता	ठेली-50/प्रतिमाह स्थाई दुकान 100/प्रतिमाह
3	मांस एवं मछली विक्रेता	100 /प्रतिमाह
4	रेस्टोरेंट	100 /प्रतिमाह
5	होटल/ लाजिंग/ गेस्ट हाउस	20 कमरे तक - 100 / प्रतिमाह 20 कमरे से ऊपर - 200/ प्रतिमाह
6	सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय /स्कूल /सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं	50/प्रतिमाह
7	समस्त बैंक	50/प्रतिमाह
8	हस्पिटल /नर्सिंग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	150/ प्रतिमाह
9	क्लीनिक (मेडिकल)/पैथोलॉजी	100/प्रतिमाह
10	स्थाई दुकानें	50/ प्रतिमाह
11	अस्थाई दुकानें (फाड़ एवं ठेला)	20 /प्रतिमाह
12	वर्कशॉप एवं कबाड़ी	50/प्रतिमाह
13	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट (रेता सरिया रोड़ा ईट पत्थर आदि)	100/प्रतिदिन /प्रतिवाहन
14	वाइन शॉप देसी	200/प्रतिमाह
15	वाइन शॉप अंग्रेजी	250/प्रतिमाह
16	बारबर, दंजी	100/प्रतिमाह
17	डाइक्लिन करने वाली दुकान	100/प्रतिमाह



18	गहने का रस पुर विप्रेता	50/प्रतिमाह
19	सार्वजनिक /निजी इथावों पर सर्कस /प्रदर्शनी /विवाह आदि प्रति आयोजन जिसमे अपशिष्ट उत्पन्न होता है	200 /प्रतिमाह

उपरोक्त वितरण के अलावा धार्मिक कार्य जैसे भडारा, जागरण, शोभा यात्रा पर उपरोक्त दरे लागू नहीं होगी

### शक्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड में यथावृत्त) धारा 29B (1) एवं नगरीय छेस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2011 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा जो रु० 2500.00 (दो हजार पांच सौ रु०) तक हो सकेगा और जब ऐसे कृत निरंतर किया जाय तो अग्रत्तर जुर्माना बिन्धा जायेगा जो प्रथम दोष सिद्ध की दिनांक के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमे अपराधों का अपराध करते रहना सिद्ध हो रु० 100.00 तक हो सकेगा, यह अधिकार अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लोहाघाट जनपद चम्पावत में निहित होगा।

मौ० इस्लाम  
अधिशासी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद  
लोहाघाट चम्पावत

गोविन्द वर्मा,  
अध्यक्ष,  
नगर पालिका परिषद  
लोहाघाट चम्पावत

## कार्यालय नगर पालिका परिषद् लोहाघाट (चम्पावत)

"प्रोटोकॉल फॉर सेप्टेज मैनेजमेंट" उपनियम-2021

28 अक्टूबर, 2022 ई0

पत्रांक 894/उपनियम एस0एम0सी0/2022-23-सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन सं0 १०/२०१५ दिनांक १० १२-२०१५ के आदेश के अनुपालन में एवं नगर पालिका अधिनियम १९१६ (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य में) की धारा २७६ में दिये गये प्राविधानों के अनुसार तथा धारा २९८ के खण्ड झ (घ) ज (घ) में दी गयी उपनियम बनाने जाने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद् लोहाघाट (चम्पावत) की बोर्ड बैठक दिनांक १२-०८-२०२१ को पारित प्रस्ताव के अनुसार उपनियम "प्रोटोकॉल फॉर सेप्टेज मैनेजमेंट" उपनियम- २०२१ बनाये जाने की स्वीकृति उपरान्त यह विज्ञप्ति इस आशय से आपत्ति/सुझाव चाहने हेतु प्रकाशित की जा रही है, जिन व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ने का रहे है।

अतः लोकहित में सुविधा, सुरक्षा एवं नियंत्रण व विनियम करने हेतु प्रोटोकॉल फॉर सेप्टेज मैनेजमेंट उपनियम - २०२१ में यदि किसी संस्था व्यक्ति, व्यक्ति विशेष, फर्म, उद्योग को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो वे इस विज्ञप्ति की प्रकाशन तिथि से ३० दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति कार्यालय नगर पालिका परिषद् लोहाघाट में प्रस्तुत कर सकता है। समय अवधि पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्ति अथवा सुझाव पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जा सकेगा जो निम्नवत है :-

प्रतिभाषा:-

1- संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख :- यह उपनियम नगर पालिका परिषद् लोहाघाट "प्रोटोकॉल फॉर सेप्टेज मैनेजमेंट" उपनियम - 2021 नियमावली कहलाएगी, जो कि विज्ञप्ति सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी। यह उपनियम नगर पालिका परिषद् लोहाघाट की सीमा के भीतर लागू होगा।

2- नगर पालिका :- नगर पालिका का आशय नगर पालिका परिषद् लोहाघाट के परिशीमन 2018 के उपरांत ०७ बार्डों की सीमा से है।

3- अधिशासी अधिकारी :- अधिशासी अधिकारी का आशय नगर पालिका परिषद् लोहाघाट के कार्यपालक अधिकारी से है।

4- अध्यक्ष :- अध्यक्ष का आशय नगर पालिका परिषद् लोहाघाट के निर्वाचित बोर्ड के अध्यक्ष से है। बोर्ड के कार्यपालक समाप्त हो जाने पर अध्यक्ष के स्थान पर अध्यक्ष / उपजिलाधिकारी, अध्यक्ष के रूप में प्रभारी अधिकारी से है।

5- सेप्टेज मैनेजमेंट सेल :- सेप्टेज मैनेजमेंट सेल का आशय नगर पालिका परिषद् लोहाघाट में सरकारी सेवा के शासन द्वारा नामित अधिकारियों के समूह की एक गठित इकाई से है जो कि सेप्टेज मैनेजमेंट सेल कहलायेगा जिसके अध्यक्ष उपजिलाधिकारी लोहाघाट होंगे तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् लोहाघाट सदस्य सचिव होंगे और अधिशासी अभियंता जल निगम, चम्पावत अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा नामित प्रतिनिधि/अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्पावत अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी एवं अवर अभियंता, नगर पालिका परिषद् लोहाघाट नामित सदस्य होंगे।

1- प्रसंग :- राष्ट्र का यह अनुभव रहा है, कि सैप्टिक टैंक और अवधाय जो डिजाइन से सम्बंधित है स्थानीय संस्थानों द्वारा वर्षों से अनुपालन किया जा रहा है, जिसके सफल सन्वातन हेतु कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है कि नगर में एक उचित वैज्ञानिक प्रबंध के मामलों में सेप्टेज तकनीकी का अनुपालन किया जाता है ताकि पर्यावरण की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सेप्टेज / फिकल स्लज सैप्टिक टैंक गड़बड़े शौचालय पर्यावरण नदी एवं अन्य पानी आदि स्रोत को प्रदूषित न करे।

1.1 राष्ट्रीय फिकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय नीति :-

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार ने एक फार्मूला प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय फिकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय नीति वर्ष २०१७ में इस दृष्टिकोण के साथ कि समस्त भारतीय शहर और नगर पूर्ण रूप से स्वच्छ तंदुरुस्त और जीवित बने रहे एवं अच्छी सफाई भी बनी रहे तथा प्रदूषण से मुक्ति मिल सके जिसके साथ उन्नत स्थल स्वच्छता से साथ ही फिकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन, ताकि सार्वजनिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य स्तर को अधिकतम प्राप्त किया जा सके और स्वच्छ वातावरण बना रहे, जिसमें विशेषकर गरीबों पर ध्यान केंद्रित किया जाये। शहरी नीति का मुख्य उद्देश्य एक स्वस्थ वातावरण प्रसन्न प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षेत्र में हो सके जैसे कि सुरक्षित और स्याई सफाई व्यवस्था एक वास्तविकता प्रत्येक आय परिवार के लिए गलियों में नगर में और शहरो में बनी रह सके।

**1.2 - उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकाल :-**

माननीय एन०जी०टी० के आदेश सं० 10 /2005 दिनांक 10-12-2015 में निम्न निर्देश निर्गत किये गये हैं जो कि उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबंधन के सम्बन्ध में हैं "उचित प्रबंध योजना या प्रोटोकॉल तैयार किया जायेगा और राज्य सरकार द्वारा समस्त एजेंसी द्वारा सूचित किया जायेगा, यह आशान्वित करने के लिए कि सीवरेज कि निकासी जो सामान्य सैप्टिक टैंक में या बायोड्राईजस्टर में एकत्रित की जाती है नियमित रूप से खाली की जाये और उसका समुचित प्रबंध किया जाये उसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार जो ख़ाद एकत्रित हुई है वह निःशुल्क किसानों को वितरित की जाये और इस उद्देश्य हेतु राज्य प्रशासन एक भागीदारी सम्बन्धित निकाय नगर पालिका परिषद लोहाघाट की होगी उपरोक्त के अनुपालन में जलापूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1984/नगर पालिका अधिनियम 1915 शहरी विकास निदेशालय जो कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के समन्वय से होगा उन्होंने एक प्रोटोकॉल सैप्टिक प्रबंधन के तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सूचित किया गया है, ताकि इसका अनुपालन शहरो/नगरो में हो सके आदेश सं० 496/(IV) (2)-810 दि० -2018-90(सा०)/18 दिनांक 22-04-2018 राज्य का सैप्टिक प्रबंधन प्रोटोकॉल राज्य और शहरो का यह दिग्दर्शन कराता है ताकि वैज्ञानिक सैप्टिक प्रबंधन बना रहे जो कि एकत्रीकरण, परिवहन, उपचार, सैप्टिज / फीकल स्लज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके इस प्रकार स्पष्ट दिशा निर्देश इस प्रोटोकाल के हैं कि प्रभावी क्रियान्वयन के लिये और आंतरिक विभागीय समन्वय हेतु मैं "सेप्टेज मैनेजमेंट सेल" का गठन का अयोजन किया गया जिसके अंतर्गत नगर पालिका परिषद लोहाघाट, पेयजल निगम, जल संस्थान होंगे

**2- नगरीय उपकानून / फीकल स्लज एवं सेप्टेज का नियमोक्तिकरण :-** सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉल के अनुसार जो शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार के शा० सं० -496/(IV) (2) - 810 दि० -2018-90(सा०)/18 दिनांक 22-04-2018 एवं समस्त लागू होने वाले नियम या कानून या समय-समय पर शासन द्वारा संशोधित नियम या नियमावली नगर पालिका लोहाघाट नियमित ढांचे को रिक्त करने, एकत्र करने, परिवहन और सेप्टेज और फीकल स्लज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि वर्णित है फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन उपनियम के अंतर्गत जो कि यहा स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पालिका परिषद लोहाघाट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सूचित किया जाता है।

**3- उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र:- इस नियमावली के उद्देश्य एवं कार्य निम्नवत हैं:-**

- 1- निर्माण सैप्टिक टैंक के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गद्दे परिवहन इलाज और सुरक्षित रखरखाव जो कि स्लेज और सेप्टेज से सम्बंधित है
- 2- क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है उसको निर्देशित करना जो कि सैप्टिक टैंक और शौचालय के गद्दे से और फीकल स्लज एवं सेप्टेज परिवहन से सम्बंधित है ताकि वे इन निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित कर सकें
- 3- उचित निरीक्षण करना और मशीनरी का अनुपालन,
- 4- लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि स्लज और सेप्टेज प्रबंधन के उचित प्रबंध हेतु है
- 5- निजी और गैरसरकारी क्षेत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन में सहभागी कि सुविधा देना

**4- एकत्रीकरण परिवहन इलाज और सेप्टिज के खुद-बुद हेतु एक प्रक्रिया अपनाना**

**4-(1) सैप्टिक टैंक और सेप्टेज / फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करना :-**

• सैप्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है , उसको हटाना और एक बार उसको ठीक करना जो कि गहराई में पहुँच गया है या बार-बार के आखिर में जो डिजायन है जो कोई भी पहले आये,

• जबकि स्लज को सुखाना और सेप्टिज टैंक में जो द्रव्य है उसको भी सुखाना /मैकेनिकल वैक्यूम टैंकर का उपयोग (जो नगर पालिका लोहाघाट द्वारा उपलब्ध कराया जाता है) नगरीय प्रबंधन द्वारा सैप्टिक टैंक का खाली करने हेतु उपयोग किया गया चाहिये

• सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉल में वर्णित है को सैप्टिक टैंक के खाली करते समय और सेप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिये

**4(2) सेप्टेज /फीकल स्लज का परिवहन :-**

- 1- फीकल स्लज और सैप्टेज ट्रांसपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे जैसा कि समय-समय पर सेप्टेज मैनेजमेंट सेल (एस०एम०सी०) द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे



### (2) फिकल स्लज और सैप्टेज फिकल निर्माता यह आश्वासन देंगे कि :-

(अ) पंजीकृत सबई वाहन जिसके अंतर्गत समस्त उपकरण जो कि परिवहन हेतु प्रयोग किये जायेंगे फिकल स्लज और सैप्टेज हेतु जो छिद्र निरोधी होगा और फिकल स्लज और सैप्टेज हेतु तालाबंद रहेगा और लागू किये जाने योग्य मानक का अनुपालन करेंगे

(ब) कोई भी टैंक और उपकरण जो कि फिकल स्लज और सैप्टेज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु प्रयुक्त नहीं करेगा ।

4(3) सैप्टेज का निष्पादन और इलाज राज्य सैप्टेज मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार नगर पालिका परिषद् लोहाघाट की अपनी में ईकाई होगी, जिसके अन्तर्गत पृथक से एक अलग सैप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जायेगा

### 5- सुरक्षा उपाय :-

(1) उचित तकनीकी संयंत्र सुरक्षा टियर का प्रयोग करते हुए मल का निस्तारण किया जाना चाहिये.

### (2) फिकल स्लज और सैप्टेज ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करें-

(अ) समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सेप्टीनेयर और यंत्र जिसके अन्तर्गत कंधे की लम्बाई तक पूरा कोटेड लियोक्रिन लायर्स, एबर बूट चेहरे का मास्क, आँखों की सुरक्षा हेतु ग्लास या शीशे जैसी कि मैनुअल स्कैवेजर और उनके पुनर्वास नियम 2013 में उल्लिखित हैं.

(ब) समस्त सुरक्षा उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जाये.

(स) समस्त मल निस्तारण कार्यकर्ताओं को सुरक्षा गियर और स्वास्थ्यवर्धक उपकरण के प्रयोग की शिक्षा दी जानी चाहिये.

(द) प्रथम सहायता किट, गैस का पता करने वाला लैंप और अग्निशमन यंत्र मल निस्तारण गाड़ी में रखे जाते हैं इसके पहले कि यह एकत्रीकरण क्षेत्र में जाता है.

(य) सैप्टिक टैंक पिट लैट्रिन में काम चल रहा है, उस समय धूम्रपान पूर्णतः वर्जित है

(र) मल निस्तारण कार्यकर्ता सैप्टिक टैंक में और शौचालय गड्ढे में प्रवेश नहीं करेंगे, और आध्यात्मिक टैंक को आना जाना रखेंगे जो कि इस कार्य का शुरु करने से पहले किया जाना आवश्यक है.

(ल) बच्चों को टैंक के ढक्कन अथवा पिट से दूर रखा जाये ताकि वे टैंक के स्क्रू और लाले से सुरक्षित रहे, कर्मचारी सावधान रहेंगे जब मल निस्तारण प्रक्रिया चल रही हो जो कि ढक्कन पर अधिक भार हेतु है, या मेन हाल का आध्यात्मन टूटने से बचा रहे

### 6- सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहन :-

6.1 नगर पालिका परिषद् लोहाघाट परिवहन वाहन को दर्ज करेगा और इसका लाइसेंस निर्गत करेगा जिजी व्यवसायियों के लिये जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो तो इस प्रकार का लाइसेंस निर्गत करने से पूर्व यह आशान्वित करेगा यह वाहन उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माध्य से सुसज्जित है तथा मानकों के अनुरूप है सेप्टेज ट्रांसपोर्टर को अपने वाहन का पंजीकरण कराने हेतु नगर पालिका परिषद् लोहाघाट के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके साथ वाहन परमिट प्रपत्र व परमिट प्रपत्र की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न करना होगा

6.2 नगर पालिका परिषद् लोहाघाट सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रांसपोर्टर द्वारा ही प्रयोग किया जायेगा, जोकि एकत्रीकरण परिवहन एवं सेप्टेज के प्रयोजन हेतु अनुमत्य है जब तक कि इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल एस०एम०सी० के साथ इन प्रोटोकॉलों में पंजीकृत नहीं है

सारणी-1 पंजीकरण व्यय

- अ- प्रारम्भिक पंजीकरण - ₹ 3,000.00 प्रतिवाहन / गाड़ी  
 ब- वार्षिक नवीनीकरण ₹ 2,000.00 प्रतिवाहन/ गाड़ी  
 स- नाम परिवर्तन/स्वामित्व का परिवर्तन - ₹ 1,500.00 प्रतिवाहन /गाड़ी  
 द- अन्य संशोधन आवश्यकतानुसार - ₹ 1,000.00 प्रतिवाहन/गाड़ी  
 (समस्त लागत दर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ेगा)

## 7- उपभोक्ता लागत और इसका संचय :-

7.1 इस क्षेत्र के समस्त मासिक ओ सैप्टिक टैंक और शौचालय के गड्डे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि नगर पालिका परिषद लोहाघाट में फिकल स्लज और सेप्टेज उपनियम में समय-समय पर दर्शाया गया है, जो कि सैप्टिक टैंक के भरने शौचालय के गड्डे, परिवहन और फिकल स्लज एवं सेप्टेज के उपाय हेतु है.

7.2 नगर पालिका परिषद लोहाघाट अपनी लागत से संशोधित करेगा जो कि समय-समय इससे सम्बंधित है ऐसी उपयोगिता लागत परिवहन फिकल स्लज व सेप्टेज के निष्कासन हेतु है.

7.3 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्थायी एकत्र किये जाये जो निम्नवत है

(अ) उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष प्रत्येक रूप से नगर पालिका परिषद लोहाघाट द्वारा वसूल किया जायेगा या नगर पालिका परिषद लोहाघाट के कोष में जमा किये जायेगा जोकि सम्बंधित भवन/ सैप्टिक टैंक मासिक से वसूल किया जायेगा.

(ब)- उपभोक्ता लागत को मासिक सिचाई लागत या संपत्ति कर में जोड़ा जायेगा अथवा एक विशेष नगरीय पर्यावरण फीस भुगतान जैसा कि कार्यक्रम के अन्तर्गत होगा करना होगा .

## सारणी -2 उपभोक्ता लागत

	भवन का वर्ग	प्रति यात्रा लागत	किराये की अधिकतम अवधि जो सैप्टिक टैंक एवं शौचालय गड्डे हेतु निर्धारित है.	मासिक दण्ड 1-5 की दर सामान्य लागत के लिए जो कि निर्धारित निस्तारण के अनुपालन हेतु होगा .
क्रम सं०	भवन का वर्ग	प्रति यात्रा लागत	कम से कम 2-3 वर्ष में एक बार जब 2 टैंक होते हैं 2/3 भाग जो भी पहले भरा जाये कम से कम	250.00
1	टैनशेड वाला मकान	2,500.00		300.00
2	अन्य समस्त मकान	3,000.00		300.00
3	दुकान	3,000.00		300.00

4-	सरकारी /निजी कार्यालय	3,000.00	प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार .	300.00
5-	बैंक	3,000.00		300.00
6-	सामुदायिक शौचालय/ मूत्रालय	4,000.00		400.00
7-	रेस्टोरेंट	3000.00		300.00
8-	होटल/ गेस्ट हॉउस (1-10 कमरे)	5 000.00		500.00
9-	होटल/ गेस्ट हॉउस (11 कमरे से अधिक)	7,000.00		700.00
10-	धर्मशाला (1-25 कमरे )	4,000.00		400.00
11-	सरकारी स्कूल /कालेज	2 500.00		250.00
12-	निजी स्कूल /कालेज	3,000.00		300.00
13-	20 व्हीलर व्हीकल शौकम	3,000.00		300.00
14-	विवाह हॉल बैंकट हॉल	5 000.00		500.00
15-	बार	5,000.00		500.00
16-	सरकारी हॉस्पिटल	3,000.00		300.00
17-	नर्सिंग होम/ क्लीनिक	3,000.00		300.00
18-	पैथोलोजी लैब	2 500.00		250.00
19-	निजी अस्पताल 20 बैड तक	5 000.00		500.00
20-	चावल मिल /अन्य मिल	5 000.00		500.00

नोट- उपरोक्त उपभोक्ता व्यय सांकेतिक है, और उनका निर्णय और स्वीकृत नगर पालिका परिषद् लोहाघाट द्वारा निर्गत किये जायेंगे

2- मल निस्तारण समयावधि में होगा, या जब टैंक 2/3 की आपूर्ति कर देता है .

(जैसा कि नगर पालिका परिषद् द्वारा स्वीकृत है.)

3- उपभोक्ता लागत 5 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ाई जायेगी .

#### 8- सैंक्रेजिजम का निरीक्षण , कियान्तरण और मजबूती देना :-

8.1 कोई भी व्यक्ति जो की एस०एस०सी० (सैंप्टिक मैनेजमेंट सेल ) / नगर पालिका परिषद् लोहाघाट द्वारा अधिकृत है उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सैंप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय, गडदे या सामुदायिक/ संस्थागत आदि का निरीक्षण करेगा.

8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और जुर्माना से प्राप्त धनराशि नगर पालिका परिषद् कोष में जमा होगी .

8.3 नगर पालिका परिषद् लोहाघाट क्षेत्र के टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेंगे

8.4 अव्येतन कार्यक्रम समय-समय पर चलाया जायेगा जो कि प्रत्येक व्यक्ति सरकार या निजी व्यवसाय के प्रशिक्षण हेतु होगी जो कि सैंप्टिक टैंक, बयोडाइजस्टर मल निस्तारण सैंप्टिक टैंक का एकत्रीकरण मशीनरी, परिवहन निष्पादन और सैंप्टिज का ईलाज .

#### 9- दण्ड :-

दण्ड का ढाचा उपकरण रहित / अकार्यशील जी०पी०एस० प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायतें फिकल स्लज का एकत्र न करना और सेप्टज ईलाज प्लांट का / भार०एन०एल० का रजिस्ट्रेशन न करना सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाडियों को अनुपालन न करना



सारणी 3 दण्ड

क्र०स०	शिवस्यत का प्रकार	दण्ड या कार्यवाही प्रपत्र इष्टया पकड़ी गई वर्ष में एक बार मल निस्तारण वाहन	दण्ड या कार्यवाही वर्ष में दोबारा पकड़ी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित	दण्ड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे बार पकड़ी गयी विशेष रूप से मूल निस्तारण वाहन
1-	लोगों की सोचनीय सेवा की शिकायत	3,000.00	8,000.00	तीन महीने के लिये परमिट सेवा की शिकायत पर परमिट का निरस्तीकरण .
2-	सेप्टेज / फिकल स्लज जैसा कि विशेष कार्य क्षेत्र में	1000.00	6 माह के लिये परमिट को स्थगित करना	तीन महीने के लिये परमिट सेवा की शिकायत पर परमिट का निरस्तीकरण.
3-	पंजीकरण न करना /पंजीकरण का नवीनीकरण न करना .	2,000.00	4,000.00	आर० टी० ओ० को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिये परमिट को स्थगित करना / परमिट का निस्तारण के लिये स्थगित करना .

शास्ति / दण्ड

नगर पालिका परिषद लोहाघाट (चम्पावत) की सीमास्तर्गत "प्रोटोकॉल फार सेप्टेज मैनेजमेंट" के अनुपालन हेतु माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन सं० 10/2015 दिनांक 10-12-2015 के आदेश के अनुपालन में तथा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299 (1) में प्रदत्त अधिकार एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे नगरवासी जो प्रोटोकॉल फार सेप्टेज मैनेजमेंट की उपविधि की किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा अथवा करता हुआ पाया जायेगा दोष सिद्ध पाये जाने पर रु० 5 000 00 (पांच हजार ) का अर्थदंड किया जायेगा उल्लंघन निरंतर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्ध होने की स्थिति में रु० 5,000 00 (पांच हजार) के अतिरिक्त प्रतिदिन रु० 100 00 (एक सौ ) की दर से अतिरिक्त अर्थदंड आरोपित किया जायेगा , अन्यथा सम्बंधित के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया जायेगा उस पर होने वाले समस्त व्ययभार वर्ज- खर्च की वसूली भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी विवाद होने की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र जिला चम्पावत होगा ,

मौ0 इस्लाम,  
अधिशासी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद लोहाघाट  
जनपद — चम्पावत

गोविन्द वर्मा,  
अध्यक्ष,  
नगर पालिका परिषद लोहाघाट  
जनपद — चम्पावत

## कार्यालय नगर पंचायत इमलीखेड़ा जिला हरिद्वार विज्ञप्ति

28 अगस्त, 2022 ई०

पत्रांक 293 / उपविधि / 2022-23- नगर पंचायत इमलीखेड़ा, जिला हरिद्वार द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1916) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश की धारा 298(2) लिस्ट (जे०) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत इमलीखेड़ा, जिला हरिद्वार द्वारा निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण एवं नियंत्रण के लिए "ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियंत्रण उपविधि 2022" बनायी गयी है, जो नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 301 उपनियम (1) के अंतर्गत जनसामान्य अथवा जिस पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला है, उनसे आपत्तियां एवं सुझाव हेतु दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के अंक 14 जुलाई 2022 में प्रकाशित हुई है, परन्तु इस उपविधि को क्रम में कोई आपत्ति व सुझाव नियत अवधि के अंदर प्राप्त नहीं हुए है।

अतः नगर पंचायत इमलीखेड़ा जिला-हरिद्वार के प्रशासक महोदय की अनुमति दिनांक 20.08.2022 द्वारा उक्त उपविधि को नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-301 उपनियम-2) के अंतर्गत उत्तराखण्ड शासकीय गजट में अंतिम प्रकाशन हेतु पुष्टि की गयी है यह उपविधि उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

### ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियंत्रण उपविधि-2022

#### 1- परिभाषाएँ-

- (क) यह उपविधि नगर पंचायत इमलीखेड़ा जनपद- हरिद्वार के "ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियंत्रण उपविधि-2022" कहलायेगी जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू एवं प्रभावी होगी।
- (ख) "निकाय" का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेड़ा, जिला-हरिद्वार से है।
- (ग) "बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत के निर्वाचित अध्यक्ष/समासदों अथवा प्रशासक से है।
- (घ) "अधिनियम"- अधिनियम का तात्पर्य उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम-1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) संशोधन एवं उपांतरण आदेश 2002 से है।
- (ङ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेड़ा, जिला-हरिद्वार के निर्वाचित अध्यक्ष अथवा प्रशासक से है।
- (च) "ठेकेदार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो नगर पंचायत इमलीखेड़ा जिला- हरिद्वार में समस्त निर्माण कार्य, पुनः निर्माण सामग्री आपूर्ति एवं अन्य कार्य जो संविदा के अंतर्गत आते हो, को करने का इच्छुक व्यक्ति/पार्स हो।
- (छ) "श्रेणी" का तात्पर्य ठेकेदार की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी से है।

#### 2- पंजीकरण की प्रक्रिया-

नगर पंचायत इमलीखेड़ा जनपद हरिद्वार के निर्माण कार्य सड़क/ नाली/ नाला/पुस्ता/अन्य निर्माण एवं भवन के निर्माण कार्यों के सम्पादन तथा सामग्री आपूर्ति हेतु ठेकेदार की तीन श्रेणियाँ होगी। इच्छुक व्यक्ति प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में निम्न शर्तों/औपचारिकताओं को पूर्ण कर अपना पंजीकरण करा सकता है-

- 1- वह भारत का नागरिक हो तथा नगर पंचायत इमलीखेड़ा जिला- हरिद्वार सीमांतर्गत या जनपद हरिद्वार में कम से कम 5 वर्ष से निवास करता हो, अथवा उत्तराखण्ड राज्य का निवासी हो, का प्रमाण-पत्र दो पासपोर्ट साईज फोटो सहित देनी होगी।
- 2 जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त द्वारा प्रदत्त अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र
- 3- जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण-पत्र (श्रेणीवार हैसियत सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है)



(क) प्रथम श्रेणी के लिए	15 00 लाख
(ख) द्वितीय श्रेणी के लिए	10.00 लाख
(ग) तृतीय श्रेणी के लिए	05 00 लाख

4- प्रथम श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु लोक निर्माण विभाग, जल विभाग, सिंचाई विभाग ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद, जल सस्थान एवं जिला पंचायत आदि विभागों में कम से कम सड़क/माली/माता आदि एवं भवन निर्माण का 05 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 50 00 लाख के अनुबंध (बाण्ड) पत्र देने होंगे। इसके अतिरिक्त स्वयं का तकनीकी अभियंता एवं टी0एण्ड0पी(मिक्सचर मशीन/ वाईब्रेटर /जे0सी0बी0/रोड रोलर/प्रिमीक्सिंग मशीन) आदि होने आवश्यक होंगे अनुभव प्रमाण पत्र अधिशासी अभियंता/अधिशासी अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।

5- द्वितीय श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु उपरोक्त विभागों में कम से कम 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में 25 00 लाख के अनुबंध (बाण्ड) पत्र देने अनिवार्य होंगे (अनुभव प्रमाण-पत्र उपरोक्तानुसार जारी ही मान्य होगा)।

6- तृतीय श्रेणी में पंजीकरण हेतु उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार के किसी भी विभाग तथा प्रथम श्रेणी के ठेकेदार द्वारा जिसके साथ कम से कम दो वर्ष का कार्य किया हो, का अनुभव प्रमाण-पत्र देना होगा।

7- प्रत्येक ठेकेदार आयकर एवं जी0एस0टी0 विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य हैं तथा आयकर एवं जी0एस0टी0 का पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

8- नगर पंचायत इमलीखेड़ा जनपद हरिद्वार में उक्तानुसार ठेकेदारी पंजीकरण का अधिकार अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत इमलीखेड़ा, जनपद हरिद्वार में निहित होगा।

### 3- जमानत-

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार स्थायी जमानत राशि राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0)/ किसान विकास पत्र/एफ0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत इमलीखेड़ा, जनपद-हरिद्वार के पक्ष नाम से बंधक कर आवेदन पत्र के साथ देनी होगी।

(क) प्रथम श्रेणी के लिए	50,000 00
(ख) " द्वितीय श्रेणी के लिए	25,000 00
(ग) तृतीय श्रेणी के लिए	15 000 00

### 4- पंजीकरण शुल्क-

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार पंजीकरण शुल्क की धनराशि नकद रूप में नगर पंचायत इमलीखेड़ा, जनपद-हरिद्वार के कोष में जमा करनी होगी।

(क) प्रथम श्रेणी के लिए	15,000.00
(ख) द्वितीय श्रेणी के लिए	10 000 00
(ग) तृतीय श्रेणी के लिए	5,000 00

### 5- पंजीकरण की अवधि-

प्रत्येक वर्ष में मात्र माह 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक ठेकेदारों के पंजीकरण किये जायेंगे। पंजीकरण हेतु निर्धारित आवेदन का प्रारूप रु0 500 00 नगर पंचायत इमलीखेड़ा, जनपद-हरिद्वार कोष में जमा कर क्रय करना होगा तथा पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही मान्य होगा, जो अवर अभियंता की सस्तुति पर अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

### 6- नवीनीकरण की प्रक्रिया-

ठेकेदारों को प्रत्येक 02 वर्ष के बाद में निम्न श्रेणी के अनुसार अपने पंजीकरण का नवीनीकरण कराना होगा।

- 1 नवीनीकरण प्रत्येक 02 वर्ष के बाद में 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक ही होगा।
- 2 नवीनीकरण से पूर्व प्रत्येक ठेकेदार को निर्धारित नवीनीकरण आवेदन पत्र के लागत रु० 250 00 निकाय कोष में जमा कराकर प्राप्त करना होगा, नवीनीकरण आवेदन पत्र के साथ चिगल वर्ष में किये गये निर्माण कार्यों का विवरण देना होगा।
- 3 नवीनीकरण शुल्क निम्न श्रेणी के अनुसार नगर पंचायत इमलीखेडा, जनपद-हरिद्वार के कोष में जमा कराने तथा विगत वर्ष में किये गये कार्यों के विवरण पर नगर पंचायत इमलीखेडा जिला-हरिद्वार के अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी-

(क) प्रथम श्रेणी के लिए	10,000 00
(ख) द्वितीय श्रेणी के लिए	7,000.00
(ग) तृतीय श्रेणी के लिए	5,000.00

4. अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी ठेकेदार के पंजीकरण के नवीनीकरण को उसके वृत्तिपूर्ण कार्य के लिए रोक सकता है।
5. नवीनीकरण के आवेदन पत्र के साथ प्रत्येक वर्ष में घरि-पत्र (जो छ माह की अवधि के अंदर का हो) तथा नवीनतम हैसियत प्रमाण-पत्र/नवीनीकरण के समय यदि हैसियत यथावत हो तो उसके लिये शपथ-पत्र देना होगा।

#### 7- निर्माण के सम्पादन के सीमा-

प्रत्येक श्रेणी के ठेकेदारों को निम्नानुसार कार्य के टेण्डर लेने का अधिकार होगा-

- 1 प्रथम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार सभी प्रकार (असीमित धनराशि के) निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकार होंगे।
- 2 द्वितीय श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार रु० 25 00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकार होंगे।
3. द्वितीय श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार रु० 15.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकार होंगे।

#### 8- निविदा प्रपत्र की लागत-

निविदा प्रपत्र का मूल्य निर्माण कार्य के व्यय अनुमान (आमरण) धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगा।

कार्यों की लागत (रुपये में)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रुपये में)
a. रु० 1,00 000 तक	100.00
b. रु० 1,00,001 से रु० 2,00,000 तक	200.00
c. रु० 200,001 से रु० 3,00,000 तक	300 00
d. रु० 300,001 से रु० 4,00 000 तक	400 00
e. रु० 400 001 से रु० 5 00 000 तक	500 00
f. रु० 500.001 से रु० 6,00,000 तक	600 00
g. रु० 600,001 से रु० 7,00,000 तक	700 00

- h. रु० 700,001 से अधिक के कार्यों के निविदा प्रपत्र का मूल्य प्रति 10000 00 पर रु० 10 00 के हिसाब से गणना कर निर्धारित कर किया जायेगा।

प्रत्येक ठेकेदार विभागीय कार्यों का ठेका लेने के लिए नगर पंचायत इमलीखेडा जनपद-हरिद्वार से निविदा प्रपत्र नकद मूल्य देकर खरीदेगा। निविदा प्रपत्र का मूल्य, जमा होने के पश्चात किसी भी स्थिति में न तो वापिस होगा और न ही आगामी निविदाओं में समायोजित होगा। निविदा प्रपत्र नगर पंचायत इमलीखेडा, जनपद-हरिद्वार के पंजीकृत ठेकेदारों को ही विक्रय किये जायेंगे।

#### 9- निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार-

ठेकेदार द्वारा खाली गई निविदाओं में न्यूनतम निविदाओं को स्वीकृत करने का

अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष का होगा किंतु यदि न्यूनतम निविदा आंकलन से ठेकेदार के 10 प्रतिशत लाभ घटाने के बाद भी कम हैं, तो इस पर तकनीकी राय लेकर निर्णय लिया जायेगा। निविदा डालने के 6 माह तक उन्हीं दरों पर कार्य करने के लिए ठेकेदार बाध्य होगा यदि ठेकेदार को निविदा डालने की तिथि से 6 माह बाद कार्यादेश दिया जाता है तो ठेकेदार उन दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होगा बिना कोई कारण बताये किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष /प्रशासी अधिकारी, नगर पंचायत इमलीखेडा जनपद हरिद्वार में निहित होगा।

#### 10- धरोहर राशि-

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रीक्यूरमेंट पॉलिसी) नियम 2017 में किये गये प्राविधान के अनुसार स्थायी जमानत/धरोहर धनराशि निविदा के साथ राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र एवं एफ0डी0आर0 के रूप में जो नगर पंचायत इमलीखेडा, जनपद-हरिद्वार के पदनाम से बंधक हो, देनी होगी।

#### 11- ठेकेदार का भुगतान-

कार्य समाप्ति के पश्चात ठेकेदार का कार्य संतोषजनक होने पर नियमानुसार बिल की धनराशि से समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार आचकर जी0एस0टी0 एवं जमानत आदि देय करी की राशि काटने के उपरांत भुगतान किया जायेगा, जमानत राशि का भुगतान 1 वर्ष बाद कार्य संतोषजनक होने पर अवर अभियंता की संस्तुति पर किया जायेगा।

#### 12- कार्य पूर्ण करने की अवधि-

प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि निविदा फार्म में दी गयी कार्य अवधि के अंतर्गत कार्य पूर्ण करें यदि समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तथा उसकी कार्य अवधि बढ़ाने हेतु ठेकेदार द्वारा समय प्राप्ति से पूर्व औचित्य स्पष्ट करते हुए प्रार्थना-पत्र दिया जाता है तो अवर अभियंता/अधिशासी अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा कार्य अवधि बढ़ाने की स्वीकृति एक बार प्रदान की जा सकती है यदि ऐसा नहीं किया गया तो ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी अवधि के लिए अवशेष कार्य पर 5 प्रतिशत की दर से अंतिम बिल की धनराशि से अर्धदण्ड के रूप में काटौती कर ली जायेगी यदि इस धनराशि की प्रतिपूर्ति बिल की धनराशि से नहीं हो पाने की स्थिति में दण्ड की अवशेष धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति सम्बंधित ठेकेदार से की जायेगी।

#### 13- पंजीकरण का निरस्तीकरण-

यदि ठेकेदार निर्धारित तिथि तक कार्य प्रारम्भ नहीं करता है अथवा कार्य संतोषजनक गुणवत्ता के अनुसार स्वीकृत स्टीमेंट व सॉर्ट प्लान के अनुरूप नहीं करता है अथवा नगर पंचायत के किसी कार्मिक के साथ अश्रवहार एवं अश्रद्धा करता है या किसी प्रकार का अनुचित दबाव डालता है, तो ऐसी स्थिति में अवर अभियंता एवं अधिशासी अधिकारी की जांच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष/प्रशासक द्वारा ठेकेदार के पंजीकरण को निरस्त कर ऐसे ठेकेदार को ब्लैक लिस्टड किया जा सकता है पंजीकरण निरस्तीकरण के फलस्वरूप ठेकेदार का ठेका स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और ठेकेदार द्वारा किये गये कार्यों का भुगतान नगर पंचायत को हुई हानि के समायोजन के पश्चात किया जायेगा।

#### 14- जमानत जम्त करने का अधिकार-

यदि ठेकेदार नगर पंचायत इमलीखेडा जनपद-हरिद्वार के उपनियमों या ठेके की शर्तों अनुबंध-पत्र का उल्लंघन कर नगर पंचायत को कोई हानि पहुँचाता है या उपविधि के नियम 13 के विपरीत कार्य करता है तो ऐसी दशा में अवर अभियंता एवं अधिशासी अधिकारी की जांच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष को ठेकेदार की जमानत जम्त करने का अधिकार होगा यदि इसके बाद भी नगर पंचायत इमलीखेडा जनपद-हरिद्वार की क्षतिपूर्ति न हो सके तो शेष राशि ठेकेदार की सम्पत्ति से भू-राजस्व के बकायों की भांति वसूल की जायेगी।

बी0एल0 आर्य,

अधिशासी अधिकारी,

नगर पंचायत इमलीखेडा हरिद्वार।

विजयनाथ शुक्ल,

प्रशासक

नगर पंचायत इमलीखेडा, हरिद्वार।



## कार्यालय नगर पंचायत इमलीखेड़ा जिला-हरिद्वार विज्ञप्ति

28 अगस्त, 2022 ई0

पत्रांक 293/उपविधि/2022-23 नगर पंचायत इमलीखेड़ा, जिला हरिद्वार की सीमान्तर्गत च0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा-298(1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-128(1)(1) के तहत भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर सम्पत्तिकर आरोपित करने के उद्देश्य से नगर पंचायत इमलीखेड़ा, जिला हरिद्वार द्वारा "सम्पत्तिकर उपविधि 2022" बनायी गयी है जो नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-301(1) के अंतर्गत जनसागान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला है, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के एक 16 जुलाई 2022 में प्रकाशित हुई है परन्तु इस उपविधि के क्रम में कोई आपत्ति व सुझाव नियत अवधि के अंदर प्राप्त नहीं हुए है।

अतः नगर पंचायत इमलीखेड़ा, जिला-हरिद्वार के प्रशासक महोदय की अनुमति दिनांक 20.08.2022 द्वारा उक्त उपविधि को नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-301 उपनियम-2 के अंतर्गत उत्तराखण्ड शासकीय गजट में अंतिम प्रकाशन हेतु पुष्टि की गयी है। यह उपविधि उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

### "सम्पत्तिकर उपविधि-2022"

#### 1- संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ:-

- (क) यह उपविधि नगर पंचायत इमलीखेड़ा, जिला-हरिद्वार "सम्पत्तिकर उपविधि-2022" कहलायेगी।
- (ख) यह उपविधि नगर पंचायत इमलीखेड़ा, जिला-हरिद्वार की सीमा में प्रवृत्त होगी।
- (ग) यह उपविधि नगर पंचायत इमलीखेड़ा जिला-हरिद्वार द्वारा प्रख्यापित अथवा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

#### 2- परिभाषाएँ- :-

किसी विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में-

- (क) "नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेड़ा जिला-हरिद्वार से है।
- (ख) "सीमा" का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेड़ा जिला-हरिद्वार की सीमा से है।
- (ग) "अधिकासी अधिकारी" का तात्पर्य अधिकासी अधिकारी नगर पंचायत इमलीखेड़ा, जिला-हरिद्वार से है।
- (घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेड़ा, जिला-हरिद्वार के अध्यक्ष/प्रशासक से है।
- (ङ) "बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेड़ा जिला-हरिद्वार के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्य अथवा प्रशासक से है।
- (च) "अधिनियम" का तात्पर्य उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम-1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) से है।
- (छ) "वार्षिक मूल्यांकन" का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-140 व धारा 141 के अंतर्गत वार्षिक मूल्य पर कर से है।
- (ज) "सम्पत्तिकर" का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-128 के अंतर्गत भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर से है।
- (झ) "समिति" का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-104 के अंतर्गत गठित समिति से है।
- (ञ) "भवन एवं भूमि" का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेड़ा, जिला-हरिद्वार की सीमांतर्गत निर्मित भवन एवं भूमि से है।
- (ट) "स्वामी" का तात्पर्य भवन एवं भूमि के स्वामी से है।
- (ठ) "अध्यासी" का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेड़ा, जिला-हरिद्वार सीमांतर्गत निर्मित भवन एवं भूमि पर किराये में रहने वाले व्यक्तियों से है।

3. **वार्षिक मूल्यांकन-** नगर पंचायत सीमांतर्गत स्थित भूमि एवं निर्मित भवन पर सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा- 141(2) के अंतर्गत कर निर्धारण के प्रयोजन के लिये नगर पंचायत द्वारा समय-समय पर पारिश्रमिक सहित या रहित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को चाहे वे सदस्य हों या न हों अथवा संस्था/एजेंसी नियुक्त किया गया या किये गये व्यक्ति/संस्था/एजेंसी ऐसे प्रयोजन के लिये किसी सम्बद्ध सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु निम्नानुसार वार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा।

(क) रेलवे स्टेशनों, कॉलेजों, स्कूलों, होटलों, कारखानों, वाणिज्यिक भवनों और अन्य अनावसीय भवनों की दशा में भवन नव-निर्माण की वर्तमान अनुमानित लागत लॉन्गविथ के प्रचलित सैंड्रिल रेट और उससे अनुत्पन्न भूमि की अनुमानित मूल्य तत्समय प्रचलित सर्किल रेट को जोड़कर निकाली गयी धनराशि का 5 प्रतिशत से अनाधिक पर वार्षिक मूल्यांकन का आकलन किया जायेगा।

(ख) खंड(क) के उपबंधों के अंतर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में यथा स्थिति भवन की दशा में प्रतिवर्ग फुट कारपेट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया दर या भूमि की दशा में प्रतिवर्ग फुट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया भवन के कारपेट क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल से गुणा किये जाने पर आए 12 गुना मूल्य से हैं और इस प्रयोजन के लिये प्रतिवर्ग फुट मासिक किराया दर पर इस प्रकार होगी जैसे कि नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार भवन या भूमि की अवस्थिति, भवन निर्माण की प्रकृति भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 के प्रयोजन के लिये कलैक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के आधार पर बोर्ड द्वारा तय किया गया जाये और ऐसे भवन या भूमि के लिए क्षेत्रफल में चालू न्यूनतम दर और अन्य कारक इस प्रकार होंगे जैसे निहित किये जाये।

(ग) खंड(क) (ख) के अंतर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में यथास्थिति ऐसे आवासीय एवं अनावसीय (दुकानात) जो किराये पर उठाये गये हों, उनका वार्षिक मूल्यांकन शहर की प्रचलित बाजार दर अथवा उस क्षेत्र के लिए कलैक्टर द्वारा तत्समय किराये हेतु प्रचलित सर्किल रेट से जो भी अधिकतम हो, के अनुसार किराये के भवन के प्रतिवर्ग फिट या मीटर मासिक किराया दर पर निर्धारण करना होगा और मासिक किराये को 12 गुना पर वार्षिक मूल्यांकन पर निर्धारण हेतु किया जायेगा।

प्रतिबंध यह है कि जहाँ नगर पंचायत की राय में असाधारण परिस्थितियों के कारण किसी भवन का वार्षिक मूल्य, यदि उपरोक्तानुसार से गणना की गयी हो अत्यधिक हो, वहाँ नगर पंचायत किसी भी कम धनराशि पर जिसमें एकरूपता औचित्य और निकाय का हित प्रतीत हो, का वार्षिक मूल्य नियत कर सकती है।

- 1- वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिये कारपेट क्षेत्र की गणना निम्नलिखित रूप से की जायेगी:-

- I. कक्ष-आंतरिक आयाम की पूर्ण माप,
- II. आच्छादित बरामदा-आंतरिक आयाम की पूर्ण माप,
- III. बालकोनी गलियारा, रसोई घर और अण्डार गृह- आंतरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप,
- IV. गैराज- आंतरिक आयाम की एक चौथाई माप,
- V. स्नानागार, शौचालय, द्वारमंडप और जीना से आच्छादित क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल का अंग नहीं माना होगा।

- 2- उप० शहरी भवन (किराये पर देने किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम-1972 के प्रयोजन के लिए किसी भवन का मानक किराया, या युक्तियुक्त वार्षिक किराये को भवन के वार्षिक गणना करते समय हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

- 3- सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु वार्षिक मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक भवन एवं भूमि के माँके पर निरीक्षण करने के उपरान्त यथास्थिति के अनुसार किया जायेगा।

- 4- भूमि/भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर कर भवन एवं भूमि के वार्षिक मूल्यांकन पर 12.5 प्रतिशत सम्पत्ति/भवन कर लिया जायेगा, परंतु निम्नलिखित भवन एवं भूमि अथवा उसके भाग निम्नानुसार कर से मुक्त रहेंगे।
- (क) मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद अथवा दूसरे धार्मिक संस्थाएं जो सार्वजनिक तथा रजिस्टर्ड ट्रस्ट या संस्था के अधीन हों, परंतु जो स्थान अथवा स्थानों के भाग रहने अथवा किराये पर या अन्य प्रकार से आय अर्जित कि जाती हैं तो उन पर कर की छूट का नियम लागू नहीं होगा।
  - (ख) अनाथालय, छात्रावास, चिकित्सालय धर्मशालाएँ तथा इस प्रकार से अन्य भवन तथा भूमि जो इस प्रकार की दान कि संस्थाओं कि सम्पत्तियों और उन्हीं संस्था द्वारा ऐसे कार्य करती हो
  - (ग) नगर पंचायत की समस्त सम्पत्तियां।
- 5- कर निर्धारण सूचियों का प्रकाशन- भूमि एवं भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर सम्पत्तिकर निर्धारण हेतु नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-141 के अधीन तैयार कि गयी सूचियों का प्रकाशन जनसामान्य के अवलोकनार्थ एवं निरीक्षण के लिए नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदर्शित कि जायेगी तथा समाचार पत्र में इस अगश्य की सूचना प्रकाशित करते हुए अधील करनी होगी कि पंचवर्षीय सम्पत्ति/भवन कर का निर्धारण किया जा चुका हैं जिस किसी व्यक्ति अथवा भवन स्वामी या अध्यासी को कर निर्धारण सूची का अवलोकन एवं निरीक्षण करना हो, वे नगर पंचायत कार्यालय में आकर कर निर्धारण सूचियों का अवलोकन एवं निरीक्षण कर सकते हैं, तथा प्रस्तावित कर निर्धारण की सूचना सम्बंधित प्रत्येक भवन स्वामी को 15 दिन के अंदर आपति प्रस्तुत करने हेतु दी जानी आवश्यक होगी और कर निर्धारण सूचियों में प्राप्त आपतियों को मोहल्ले/वार्ड वार क्रम संख्या देते हुए आपति एवं निस्तारण पंजिका में अंकित किया जायेगा।
- 6- आपतियों का निस्तारण- भूमि एवं भवन के वार्षिक मूल्यांकन अथवा सम्पत्तिकर निर्धारण पर प्राप्त आपतियों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु नगर पालिका अधिनियम-1916 कि धारा-104 के अंतर्गत गठित समिति अथवा समिति गठित न होने कि स्थिति में अधिशासी अधिकारी बोर्ड द्वारा नगर पालिका अधिनियम-1916 कि धारा-112 के अंतर्गत शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के उपरांत निम्न प्रकार से किया जायेगा।
- प्राप्त आपतियों की सुनवाई हेतु तिथि एवं समय नियत करते हुए आपतिकर्ता को लिखित सूचना प्रेषित करनी होगी।
  - i। आपतियों के निस्तारण कि स्थिति एवं निर्णय सम्बंधित पत्रावली अथवा आपति निस्तारण पंजिका में जस्टीफिकेशन के साथ दर्ज करनी होगी।
  - ii। शासनदेश सं० 2054/नौ-9-97-79ज/97 दिनांक 28.06.1997 द्वारा वार्षिक मूल्यांकन एवं कर निर्धारण पर प्राप्त आपतियों की सुनवाई और निस्तारण दिये गये निर्देशानुसार दी जायेगी।
- 7- कर निर्धारण सूचियों का अभिप्रमाणीकरण और अभिरक्षा-
- (क) अधिशासी अधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, नगर पंचायत क्षेत्र या उसके किसी भाग के क्षेत्रवार किराया दरों और निर्धारण सूची को अपने हस्ताक्षर अभिप्रमाणित करेगा।
  - (ख) इस प्रकार से अभिप्रमाणित सूची को नगर पंचायत कार्यालय में जमा की जायेगी।
  - (ग) जैसे ही सम्पूर्ण नगर क्षेत्र की सूची इस प्रकार से जमा कर दी जाये वैसे ही निरीक्षण हेतु खुले होने के लिये सार्वजनिक सूचना द्वारा घोषणा की जायेगी,
  - (घ) कर निर्धारण सूचियों में उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही होने के उपरांत सम्पत्ति/भवनकर भाग एवं वसूली पंजिका में अंतिम रूप से सूची में दर्ज करते हुए नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-166 के अंतर्गत दावों की वसूली हेतु अग्रतर कार्यवाही शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशानुसार करनी होगी।
- 8 सम्पत्तिकर निर्धारण की औपचारिकताये पूर्ण होने के पश्चात सम्पत्तिकर कि वार्षिक माग के सापेक्ष प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक सम्पत्ति/भवन कर की धनराशि भवन स्वामी/अध्यासी को पंचायत कार्यालय अथवा निकाय द्वार वसूली हेतु अधिकृत कार्मिक को जमा कर रसीद प्राप्त करनी होगी यदि सम्पत्तिकर/भवन



- कर की धनराशि 31 मार्च तक जमा नहीं होती है तो बकाया धनराशि पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत अधिभार देना होगा, अन्यथा बकाया धनराशि अधिभार सहित भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र (आर० सी०) जिलाधिकारी को प्रेषित कर दी जायेगी।
- 9- सम्पत्तिकर की वार्षिक मांग के सम्बन्ध प्रत्येक वर्ष में 31 अक्टूबर तक सम्पत्ति/भवन कर की धनराशि एक मुश्त जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी जो बकाया सम्पत्तिकर के बकायादादा पर लागू नहीं होगी।
- 10-कोई भी व्यक्ति किसी समय भवनों कि ऐसेसमेंट सूची पर अपना नाम बतौर स्वामी दर्ज करा सकता हैं और जिस समय तक आवेदन पत्र को अस्वीकार करने का काफी कारण न हो उसका नाम दर्ज कर लिया जावेगा, अस्वीकृति का कारण लिख दिया जायेगा।
- 11-जब तक इस बात में शक हो कि भवन या भूमि पर की जिसका नाम स्वामी के रूप में दर्ज किया जाये तो बोर्ड या समिति या वह अधिकारी जिसकी बोर्ड ने उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा 143(3) के अधीन अधिकार दिया हो, यह तय करेगा कि किसका नाम स्वामी के तौर पर दर्ज होना चाहिए इसका निश्चय उस समय तक लागू रहेगा जब तक सक्षम न्यायालय उसको रद्द न कर दे
- 12-(1) अगर किसी ऐसे भवन या भूमि के स्वामी होने क अधिकार जिस पर यह कर लागू हो, हस्तांतरित किया जावे तो अधिकार हस्तांतरित करने वाला या जिसको हस्तांतरित किया जावे, वह यदि कोई दस्तावेज न लिखी गयी हो तो अधिकार लेने की तिथि से और लिखी गयी हो तो दस्तावेज लिखे जाने या रजिस्ट्री होने या हस्तांतरित होने की तिथि से तीन माह के अंदर हस्तांतरित होने कि सूचना अध्यक्ष अथवा अधिशासी अधिकारी को देगा।
- (2) किसी ऐसे भवन या भूमि का स्वामी जिस पर कर लागू है, की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी या जो जायदाद का स्वामी हो इसी प्रकार स्वामी होने से तीन माह के अंदर सूचना देगा।
- 13- (1) सूचना में जिसका विवरण पहले दिया गया, उक्त नियम में उल्लिखित सभी विवरण सफाई से और ठीक तौर से दिये जायेंगे
- (2) हर ऐसा व्यक्ति जिसको जायदाद हस्तांतरित की गयी हो, अधिशासी अधिकारी के मांगने पर दस्तावेज(अगर लिखी गयी हैं) या उसकी एक प्रतिलिपि जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1877 ई० के अनुसार हो गयी हो पेश करेगा,
- 14-सम्पत्तिकर निर्धारण सूचियों में संशोधन और परिवर्तन-
- नगर पालिका अधिनियम-1916 कि धारा-147 के अंतर्गत अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी किसी भी समय सम्पत्तिकर निर्धारण सूचियों में संशोधन एवं परिवर्तन करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्र निम्नलिखित रूप में निस्तारित किया जायेगा
- (क) उसमें किसी ऐसे व्यक्ति व ऐसी सम्पत्ति का नाम जिसकी प्रविष्टि होनी आवश्यक थी या किसी ऐसी सम्पत्ति जो कर निर्धारण सूची में अधिप्रमाणीकृत होने के पश्चात कराधान के लिये दाई हो गई हो प्रविष्टि करके, या
- (ख) उसमें किसी सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी के नाम के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का नाम जिसने अंतरण द्वारा या अन्य प्रकार से सम्पत्ति का स्वामित्व या अध्यासन का उत्तराधिकार प्राप्त किया हो, प्रतिस्थापित करके, या
- (ग) किसी सम्पत्ति के जिसका (जिसका मूल्यांकन या कर निर्धारण गलत हो गया हैं या जिसका मूल्यांकन या निर्धारण कपट, मिथ्या व्यपदेशन या त्रुटि के कारण गलत किया गया हैं) मूल्यांकन या कर निर्धारण में वृद्धि करके, या
- (घ) किसी सम्पत्ति का जिसका मूल्य भवन में किये गये परिवर्धन या परिवर्तन के कारण बढ़ गया हो, पुनः मूल्यांकन या पुनः कर निर्धारण करके, या
- (ङ) जहाँ वार्षिक मूल्य का, जिस पर कोई कर उद्ग्रहीत किया जाना हो, प्रतिशत( नगर पालिका या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी) द्वारा धारा-136 के उपबंधों के अधीन परिवर्तित कर दिया गया हो वहाँ प्रत्येक मामले में देय कर की धनराशि में तदनुसृत परिवर्तन करके, या
- (च) स्वामी के आवेदन-पत्र देने पर या ऐसे संतोषप्रद साक्ष्य पर कि स्वामी का पता नहीं चल रहा हैं, और कभी करमे की आवश्यकता सिद्ध कर दी गयी है, स्वप्रेरणा से किसी ऐसे भवन से जो

पूर्णतः या अंशतः लोड दिया गया हैं या नष्ट कर दिया गया हैं, मूल्यांकन में कमी करके या (छ) किसी लिपिकीय गणना सम्बन्धी या अन्य प्रत्यक्ष भूल को ठीक करके।

प्रतिबन्ध- यह हैं कि किसी हितबन्धी व्यक्ति को ऐसे परिवर्तन की जिसे नगर पंचायत या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी की उपरोक्त खण्ड-क,ख ग, द घ के अधीन करने का प्रस्ताव करें या उस दिनांक के सम्बन्ध में जब उक्त परिवर्तन किया जायेगा कम से कम एक मास की नोटिस देगी।

- 1- नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 143 की उपधारा(2) और (3) के उपबन्ध जो तदन्तर्गत वर्णित आपतियों पर लागू होते हैं यथासम्भव, उपधारा-2 के अधीन की गयी नोटिस के अनुश्रवण की गयी किसी आपति पर धारा-147 की उपधारा-1 के खण्ड(घ) लागू होंगे।
- 2- अधिनियम की धारा-147 की उपधारा-1 के अधीन किया गया प्रत्येक परिवर्तन धारा-144 के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों के हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जायेगा तथा धारा-160 के अधीन की गयी अपील के अधीन रहते हुए उस दिनांक से प्रभावी होगा जब अगली किश्त देय हो।
- 3- सम्पत्तिकर निर्धारण सूचियों में परिवर्तन हेतु विरासतन, उत्तराधिकारी, मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं बटवारा आदि के लिये परिवर्तन शुल्क रु० 2500.00, आवासीय एवं व्यावसायिक हेतु रु० 5000.00 होगा
- 4- सम्पत्तिकर निर्धारण सूचियों में रजिस्टर्ड बैनामा पर अंकित प्रचलित सर्वेक्ष रेट की लागत पर 2 प्रतिशत परिवर्तन शुल्क जो उपरोक्त आवासीय के लिये रु० 2500.00 व्यावसायिक के लिये रु० 5000.00 से कम नहीं होगा।

15- उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-151(1) से (5) तक दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत अध्यासन के कारण सम्पत्तिकर में तदनुसार छूट प्रदान की जायेगी;

#### शास्ति

उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-299(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार एतद् द्वारा निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधि उल्लंघन करने के लिये अर्थदण्ड रु० 1000.00(रु० एक हजार) तक हो सकता है और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहा हो तो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक से ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिनके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, अतिरिक्त जुर्माना किया जा सकता है, जो रु० 100.00(रु० एक सौ) प्रतिदिन तक हो सकता है

बी०एल० आर्य,  
अधिशासी अधिकारी,  
नगर पंचायत इमलीखेडा हरिद्वार।

विजयनाथ शुक्ल,  
प्रशासक,  
नगर पंचायत इमलीखेडा, हरिद्वार।

## कार्यालय नगर पंचायत इमलीखेडा जिला हरिद्वार विज्ञप्ति

26 अगस्त, 2022 ई०

पत्रांक 293/उपविधि/2022-23 नगर पंचायत इमलीखेडा जिला हरिद्वार की सीमान्तर्गत उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 298(2) सूची(क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला हरिद्वार की सीमान्तर्गत भवन निर्माण, पुनर्निर्माण एवं परिवर्तन आदि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से नगर पंचायत इमलीखेडा जिला हरिद्वार द्वारा "भवन निर्माण, पुनर्निर्माण एवं परिवर्तन उपविधि 2022" बनायी गयी है, जो नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-301(1) के अंतर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला है, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के अंक 14 जुलाई 2022 एवं हिंदी सप्ताहिक हिमालयन एक्सप्रेस 04 जुलाई 2022 के अंक में प्रकाशित हुई है, परन्तु इस उपविधि के क्रम में कोई आपत्ति व सुझाव नियत अवधि के अंदर प्राप्त नहीं हुए है।

अतः नगर पंचायत इमलीखेडा जिला-हरिद्वार के प्रशासक महोदय की अनुमति दिनांक 20.06.2022 द्वारा उक्त उपविधि को नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-301 उपनियम-(2) के अंतर्गत उत्तराखण्ड शासकीय गजट में अंतिम प्रकाशन हेतु पुष्टि की गयी है। यह उपविधि उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

### "भवन निर्माण, पुनर्निर्माण एवं परिवर्तन उपविधि-2022"

#### 1- सक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ:-

- (क) यह उपविधि नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार "भवन निर्माण पुनर्निर्माण एवं परिवर्तन उपविधि-2022" कहलायेगी।
- (ख) यह उपविधि नगर पंचायत इमलीखेडा जिला-हरिद्वार की सीमा में प्रवृत्त होगी।
- (ग) यह उपविधि नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार द्वारा प्रख्यापित अथवा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

#### 2- परिभाषाएँ

किसी विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में-

- (क) "नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार से है।
- (ख) "सीमा" का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेडा जिला-हरिद्वार की सीमा से है।
- (ग) "अधिकांसी अधिकारी" का तात्पर्य अधिकांसी अधिकारी नगर पंचायत इमलीखेडा जिला-हरिद्वार से है।
- (घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार के अध्यक्ष/प्रशासक से है।
- (ङ) "बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्य अथवा प्रशासक से है।
- (च) "अधिनियम" का तात्पर्य उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम-1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) से है।
- (छ) "निकाय" का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार से है।

3- नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-178 की उपधारा (2) के अभिदेश के अनुसार यह चाहती है कि निकाय की सीमान्तर्गत प्रत्येक प्रकार के भवन निर्माण की सूचना निम्न उपनियमों के अधीन निकाय को दी जाये।

4- भवन निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मुख्य परिवर्तन के विचार की सूचना निम्नलिखित उपनियमों के अनुसार दी जायेगी मानचित्र को डिप्टी/डिप्लोमा धारी इंजीनियर जिसका प्रदेश में पंजीकरण हो तथा सचिव उत्तराखण्ड शासन अवाप्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 2269/V/आ०-2007-55(आ०)/2006 टी०सी० दिनांक 06 नवम्बर, 2007(समय समय पर सशोधित) में निर्धारित मानकों का पालन करते हुए मानचित्र तैयार किया जायेगा।



- 5- 1 मीटर के बराबर 1 सेंटीमीटर पैमाने में मानचित्र तैयार किया जायेगा जिसमें भवन की स्थिति तथा चित्रों के साथ तत् सम्बन्धित भवन का उत्तरी बिंदु स्पष्ट रूप से दिखाया जायेगा, मानचित्र पर आवेदक के हस्ताक्षर होंगे, इस मानचित्र में वह पूर्ण विवरण होगा, जिसमें निकाय प्रस्तावित भवन की उपयुक्तता पर विचार कर सके मानचित्र में निम्नलिखित विवरण विशेष रूप से दिखाये जाने चाहिए-
- (क) प्रस्तावित भवन को उससे मिलने वाली सड़को, गलियों, दूसरे भवनों तथा जायदाद से सम्बन्धित स्थिति तथा मौहल्ला लिखना चाहिये उसमें मिलने वाली गलियों और चौड़ाई भी लिखनी चाहिए, ऐसी दशा में जब कि सड़को तथा गलियों की चौड़ाई एक सी न हो तो कम से कम चौड़ाई भी दिखाई जानी चाहिए
  - (ख) समस्त कुओं, पानी की पाइप लाइनों शौचालयों तथा अन्य सफाई व्यवस्थाओं की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखायी जाये
  - (ग) मानचित्र में निम्नलिखित बातें भी दिखायी जाये-
    - (i) गृह तालाब, भवन की स्थिति से सम्बन्धित सड़क या जायदाद और खाली पड़े स्थान
    - (ii) पहली या ऊपरी सतह तथा प्रत्येक अतिरिक्त सतह।
    - (iii) मकान के मुख्य अगले भाग की कुर्सी।
  - (घ) मानचित्र में समस्त गये काम प्रथम रंगों से दिखाई जाये और इनमें प्रयोगित रंगों की तालिका भी मानचित्र में होनी चाहिए
  - (ङ) किसी भी भवन में संज्ञा अथवा खुला शौचालय बनाने की अनुमति नहीं दी जायेगी
- 6- कोई शौचालय साप्ताहिक सड़क की ओर नहीं खुलने दिया जायेगा, जब तक कि 1.50 मीटर ऊँचा अतिरिक्त दरवाजा या 1.50 मीटर ऊँची दीवार इस स्थिति के साथ न बनायी जाये कि अतिरिक्त दरवाजा या दीवार द्वारा शौचालय से पर्दा न किया हो
- 7- प्रत्येक शौचालय व मूत्रालय का फर्श जो पक्के मकान से सम्बन्धित हो वह बिना चमकदार पॉलिश की हुई टाइल्स, पत्थरी प्लेटों पक्का सीमेंट प्लास्टर अथवा न घुलने वाले मसाले से जिनकी मोटाई 2 सेंटीमीटर से कम न हो, नहीं बनाया जायेगा
- 8- पक्के मकानों की नालियाँ जिनमें होकर मकान का गंदा पानी जाता है वह पक्के मिट्टी के अथवा अर्ध गोलाकार बर्तन से व सीमेंट से प्लास्टर की हुई ईंटों से बनायी जायेगी।
- 9- तंग गलियों में पक्के मकानों के पतनाले होंगे/तोहे के पतनाले अथवा निचले नलों के पतनाले होंगे जिसमें बंद होकर छत, छज्जा या अन्य प्रक्षेपणों का पानी निकास जायेगा। तोहे के बंद पतनाले या निचले नल मजबूती के साथ लगवाये जायेंगे जिसके निचले भाग में कोहनी होगी। चौड़ी सड़कों में उस सड़क पर प्रत्येक पतनाले के नीचे पत्थर कि शिला डाली जायेगी
- 10- धारा-181 के संदर्भ में उल्लिखित अनुमति की अवधि एक वर्ष होगा तथा प्राप्त स्वीकृति की समाप्ति के पश्चात कार्य नहीं किया जायेगा। जब तक दोबारा स्वीकृति के लिये आवेदन न किया गया हो।
- 11- स्वीकृति चाहने वाले कार्यों का निरीक्षण अधिशासी अधिकारी या निकाय द्वारा अधिकृत कर्मचारी किसी भी समय किसी कार्य को जबकि उसका निर्माण किया जा रहा हो अथवा यह सूचना कि कार्य पूरा हो चुका है प्राप्त होने के एक महीने के अंदर अथवा ऐसी सूचना के प्राप्त होने पर कार्य की समाप्ति के पश्चात किसी क्षण भी निरीक्षण कर सकता है
- 12- मानव निवास के लिये बनाया हुआ अथवा मानव निवास में प्रयुक्त होने वाले कमरे में कम से कम 2 हवादार खिड़किया होंगी, जिनका पूरा क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा
- 13- जबकि मकान मानव निवास के काम आता हो उसकी भूमि में तिहाई क्षेत्रफल से अधिक पर मकान नहीं बनाया जायेगा किंतु 2 भंजिले मकान में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
- 14- मकान की कुर्सी का सबसे निचला भाग सामने वाली सड़क पर सबसे ऊँचे बिंदु कम से कम 40 सेंटीमीटर ऊँचा होगा और उसकी स्वीकृति देने वाले अधिकारी की सतुष्टि के अनुसार पानी बाहर जाने का प्रबंध होगा

- 15- किसी सड़क गली गलियारे या मुहाने से भवन का अगला स्थान पूरी लम्बाई से कम से कम 1.25 मी० खुला होगा यदि वह सड़क गली या गलियारे किसी पार्क या विकास क्षेत्र को जाती हो तो वह स्थान 1.5मी० खुला होगा इस स्थान पर चबूतरा, मेहरा अथवा अन्य प्रक्षेपण जो बाहरी हवा के लिये खुला रहे, कुछ नहीं बनाया जायेगा।
- 16- निकाय के अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह दी गयी स्वीकृति को रद्द कर सकता है संशोधन कर सकता है यदि यह ज्ञात हो जाये कि स्वीकृति धोखे अथवा मिथ्या कथन के फलस्वरूप हो गयी थी तो ऐसा किया गया कार्य बिना स्वीकृति के किया गया कार्य समझा जायेगा किंतु प्रतिबंध यह है कि स्वीकृति को रद्द करने अथवा संशोधन करने के पूर्व निकाय द्वारा सम्बन्धित पक्ष को सुनने के लिये उपयुक्त अवसर प्रदान करेगी।
- 17- (अ)- कोई भी व्यक्ति भवन निर्माण पुनर्निर्माण अथवा उसमें मुख्य परिवर्तन आदि का कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं करेगा जब तक की वह धारा-178 के अनुसार सूचना न दी हो तथा निकाय द्वारा स्वीकृति प्राप्त न हुई हो व निम्न शुल्क नगर पंचायत के कार्यालय में जमा न कर दिया हो।
- I. नया भवन भूमि तल के निर्माण के लिये रु० 50 प्रति वर्ग मी०
  - II भवन का पुनर्निर्माण अथवा उसमें कोई परिवर्तन करने के लिये रु० 20 प्रति वर्ग मी०
  - III. भूमि तल के बाद भवन निर्माण प्रति तल रु० 30 प्रति वर्ग मी०।
- (ब)- कोई भी व्यक्ति/ फर्म या कम्पनी व्यावसायिक/शैक्षिक/चिकित्सा संस्थागत एवं सामुदायिक सुविधाएँ/औद्योगिक एवं अन्य विविध प्रकार के भवन निर्माण पुनर्निर्माण अथवा उसमें मुख्य परिवर्तन आदि का कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं करेगा जब तक कि धारा-178 के अनुसार सूचना न दी हो अथवा निकाय द्वारा स्वीकृति प्राप्त न हुई हो व निर्धारित शुल्क नगर पंचायत में जमा न कर दिया हो।
- 18- मनोरंजन के किसी स्थान के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में-  
सार्वजनिक मनोरंजन के किसी भवन के निर्माण अथवा उसमें परिवर्तन करने की स्वीकृति निकाय द्वारा बिना राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के नहीं दी जायेगी यदि ऐसे भवन के निर्माण स्थल अथवा प्रस्तावित निर्माण स्थल-
- (क)- निम्नलिखित की एक फलान अर्थात्वास में है-
- I. कोई आवासीय संस्था जो किसी भी अभिजात शिक्षा संस्था जैसे कॉलेज या लड़कियों के स्कूल से संलग्न हो या
  - II. कोई सार्वजनिक अस्पताल जिसमें भर्ती होकर चिकित्सा कराने वाले रोगियों के लिये एक बड़ा कक्ष अथवा
  - III. कोई अनाथालय जिसमें 100 या उससे अधिक व्यक्ति रहते हो जो किसी धनी आबादी के ऐसे आवासीय क्षेत्र में हो जो या तो केवल आवास के प्रयोजन के लिए हो अथवा व्यापारिक प्रयोजनों से धनी आवासीय प्रयोजनों के लिये सुरक्षित हो या सामान्यतः प्रयुक्त होता हो या किसी ऐसे क्षेत्र में जो किसी विधि के अधीन किसी गृह निर्माण अथवा नियोजन की योजना द्वारा अन्य प्रकार के आवासीय प्रयोजनों के लिये सुरक्षित हो किंतु प्रतिबंध यह है कि चलचित्रों के प्रदर्शनार्थ प्रयुक्त किए जाने के लिये अभिप्रेत किसी भवन के निर्माण की आज्ञा उस समय तक नहीं दी जायेगी जबतक निकाय को यह समाधान न हो जाये नक्शों तथा उसकी प्रविष्टियों के सम्बन्ध में सिनेमा फोटोग्राफर एक्ट 1916 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी हो।
- 19- निम्नलिखित शुल्क से मुक्त रहेंगे-
- (क)- मंदिर मस्जिद, गिरजा घर, गुरुद्वारा (भवनों का निर्माण इनसे सम्बन्धित व्यावसायिक व अन्य धार्मिक स्थान व संस्थाएँ सम्मिलित नहीं होंगे)

## शास्ति

उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम-1916 (उत्तराखंड में यथा प्रवृत्त) की धारा-299(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नगर पंचायत इमलीखेडा जिला-हरिद्वार एतद् द्वारा निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधि उल्लंघन करने के लिये अर्थदण्ड रु० 10000 00(रु० दस हजार) तक हो सकता है और यदि उल्लंघन निरंतर जारी रहा हो तो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक से ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिनके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, अतिरिक्त जुर्माना किया जा सकता है जो रु० 500.00(रु० पांच सौ) प्रतिदिन तक हो सकता है।

बी०एल० आर्य,  
अधिशाली अधिकारी,  
नगर पंचायत इमलीखेडा, हरिद्वार।

विजयनाथ शुक्ल,  
प्रशासक  
नगर पंचायत इमलीखेडा, हरिद्वार।



## कार्यालय नगर पंचायत इमलीखेडा जिला हरिद्वार विज्ञप्ति

28 अगस्त, 2022 ई0

पत्रांक 293/उपविधि/2022-23 नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला हरिद्वार सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-288 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की उपधारा-2 खण्ड-(ज)(च) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत इमलीखेडा द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-128 के उपधारा-1(ii)(iii) एवं धारा-284 के तहत विभिन्न व्यापार और आजीविका पर लाइसेंस शुल्क आरोपित करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या 398/वीं-85-204(जनरल)/94 दिनांक 20.10.1994 के अनुसार विभिन्न व्यवसायों हेतु "व्यवसायिक लाइसेंस एवं शुल्क वसूली उपविधि-2022" बनायी जाती है जो नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-301(1) के अंतर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला है, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के अंक 16 जुलाई 2022 में प्रकाशित हुई है, परन्तु इस उपविधि के क्रम में कोई आपत्ति व सुझाव निरस्त अवधि के अंदर प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः नगर पंचायत इमलीखेडा जिला-हरिद्वार के प्रशासक महोदय की अनुमति दिनांक 20.06.2022 द्वारा उक्त उपविधि को नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-301 उपनियम-(2) के अंतर्गत उत्तराखण्ड शासकीय गजट में अंतिम प्रकाशन हेतु पुष्टि की गयी है। यह उपविधि उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

### "व्यवसायिक लाइसेंस एवं शुल्क वसूली उपविधि-2022"

#### 1- संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ:-

- (क) यह उपविधि नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार "व्यवसायिक लाइसेंस एवं शुल्क वसूली उपविधि-2022" कहलायेगी।
- (ख) यह उपविधि नगर पंचायत इमलीखेडा जिला-हरिद्वार की सीमा में प्रवृत्त होगी।
- (ग) यह उपविधि नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार द्वारा प्रख्यापित अथवा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

#### 2- परिभाषाएँ:-

किसी शिष्य या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में-

- (क) "नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेडा जिला-हरिद्वार से है।
- (ख) "सीमा" का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेडा जिला-हरिद्वार की सीमा से है।
- (ग) "अधिकांसी अधिकारी" का तात्पर्य अधिकांसी अधिकारी नगर पंचायत इमलीखेडा जिला-हरिद्वार से है।
- (घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेडा जिला-हरिद्वार के अध्यक्ष/प्रशासक से है।
- (ङ) "बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेडा जिला-हरिद्वार के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्यों से है।
- (च) "अधिनियम" का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) संशोधन एवं उपांतरण आदेश-2002 से है।
- (छ) "लाइसेंस" का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेडा जिला-हरिद्वार की सीमान्तर्गत किये जाने वाले विभिन्न व्यापार और आजीविका के लाइसेंस दिये जाने एवं उनसे निर्धारित शुल्क वसूली से है।
- (ज) "ट्रैंड लाइसेंस" का तात्पर्य अधिसूचना संख्या 1334/IV (2)-शं०वि०-2020-17(सां०)/20 दिनांक 10.12.2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड नगर पालिका एवं नगर पंचायत परिष्करण उपविधि 2020 से है।
- (झ) "अवधि" का तात्पर्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष अथवा (1 अप्रैल से 31 मार्च) 1 वर्ष के लिये तक दिये जाने वाले व्यवसायिक लाइसेंस से है।

#### 3- लाइसेंस- आवेदक द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ दो फोटो(पासपोर्ट साइज) खींची होनी तथा आवेदन में व्यवसाय का मद एवं विवरण भी देना होगा।

- 4- प्राप्त आवेदन पत्र पर नगर पंचायत द्वारा समुचित विचारोपरांत 15 दिवस के अंदर शुल्क लेकर लाइसेंस दिये जाने का निर्णय लिया जायेगा, जिसकी सूचना आवेदक को दी जायेगी।
- 5- सूची में वर्णित व्यावसायिक लाइसेंस 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के बीच व्यवसायी द्वारा प्रत्येक दश में बनाया जाना अनिवार्य होगा। इस लाइसेंस की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च (एक वित्तीय वर्ष) तक वैध होगी अन्यथा स्थिति में विलम्ब शुल्क जो 10 प्रतिशत लाइसेंस अधिकारी द्वारा निर्धारित करते हुये वसूल किया जायेगा।
- 6- लाइसेंस जारी करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।
- 7- जांचकर्ता के जांच के समय व्यवसाय के सम्बन्धित सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आवेदनकर्ता का होगा।
- 8- लाइसेंस अधिकारी स्वयं अथवा अपनी एजेंसी, अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जांच का कार्य सम्पादित करा सकता हैं, जो नगर पंचायत के कर निरीक्षक स्तर से कम नहीं होगा।
- 9- लाइसेंस धारक अपना व्यवसाय बदलता है तो उसकी सूचना अनिवार्य रूप से एक माह के अंदर नगर पंचायत में अपने पुराने लाइसेंस विवरण के साथ लिखित रूप में उपलब्ध करा देगा।
- 10- उक्त सूची में वर्णित लाइसेंसों के नियमों का उल्लंघन होने की दशा में लाइसेंस अधिकारी जनहित में किसी भी समय लाइसेंस निरस्त कर सकता है। लाइसेंस अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करता है तो उस अपील की सुनवाई का अधिकार अध्यक्ष नगर पंचायत इमलीखेडा, हरिद्वार में निहित होगा।
- 11- व्यावसायिक लाइसेंस की दरें प्रतिवर्ष निम्नवत् होगी, जो व्यापारी/व्यक्ति लाइसेंस नहीं बनाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए बकाया लाइसेंस की धनराशि की वसूली 10 प्रतिशत सर-चार्ज सहित भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र (आर० सी०) जिलाधिकारी को प्रेषित कर दी जायेगी।

### व्यावसायिक लाइसेंस शुल्क की दरें

क्र० सं०	मद्य का नाम	लाइसेंस शुल्क की प्रस्तावित दर वार्षिक
1	2	3
1	होटल लाजिंग/ गेस्ट हाउस/आश्रम 10 रैंया तक	1000.00
2	होटल लाजिंग/ गेस्ट हाउस/आश्रम 11 से 20 रैंया तक	2000.00
3	तीन सितारा होटल अथवा बिना स्टार 20 रैंया से 30 रैंया तक	5000.00
4	उपरोक्त 31 रैंया से 40 रैंया तक	6000.00
5	उपरोक्त 41 रैंया से 50 रैंया तक	10000.00
6	उपरोक्त 50 रैंया से ऊपर	12000.00
7	तीन सितारा होटल	15000.00
8	पांच सितारा होटल	20000.00
9	रेस्टोरेंट उच्च श्रेणी	5000.00
10	रेस्टोरेंट मध्यम श्रेणी	3000.00
11	रेस्टोरेंट सामान्य श्रेणी	2000.00
<b>परिवहन</b>		
12	घोड़ा तांगा	100.00
13	रिक्शा किराये पर	300.00
14	रिक्शा (निजी चालित)	200.00
15	टैला/ठैली	300.00

16	हाथ ठेली	250 00
17	बैलगाड़ी/भैंसागाड़ी	200.00
18	ट्रेक्टर ट्रॉली/छोटा हाथी	500-00
19	अन्य चार पहियों के वाहन(व्यावसायिक प्रयोग हेतु सभी वाहन)	500 00
20	मोटर गैराज	1500 00
21	स्कूटर गैराज/रिपेयर शॉप	1000.00
22	मोटर वाहन एजेंसी(सेल्स/सर्विस)	5000 00
23	स्कूटर एजेंसी(दो पहिया/तीन पहिया)	2000.00
24	साइकिल की दुकान	1000.00
पेट्रोलियम		
25	पेट्रोल/डीजल पम्प थोक विक्रेता कम्पनी	10000.00
26	पेट्रोल/डीजल पम्प फुटकर विक्रेता	5000 00
27	जनरेटर, डीजल/पेट्रोल	1000.00
28	दुकान अन्य पेट्रोलियम उत्पादन	1000 00
अन्य व्यवसाय		
29	नर्सिंग होम/अस्पताल	2000 00
30	क्लीनिक	500 00
31	मेडिकल स्टोर	1000 00
32	कृषि यन्त्र दवाइयों एवं फर्टीलाइजर	1000 00
33	धुलाई गृह (लान्ड्री)	1000.00
34	ड्राई क्लीनर	2000 00
35	फाइनेंस कम्पनी, पिट फंड	8000 00
36	इन्सुरेंस कम्पनी, प्रतिशाला	10000.00
37	फाउंडिंग इंजीनियरिंग इंस्टिट्यूट	2000 00
38	आईस फैक्ट्री तथा कोल्ड ड्रिक्स सोडा ऐस्टेट वाटर फैक्ट्री	2000 00
39	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	2000.00
40	आटा चक्की	1000.00
41	गूदड़/गुड़ गोदाम	1000 00
42	कंकड़ तथा सुखी की भट्टी	2000.00
43	धूना	1000.00
44	ईट का भट्टा	10000.00
45	सामुन फैक्ट्री	2000 00
46	लोहा व्यापारी, टिम्बर, सीमेंट, ईटा बालू (थोक मोरग, मारवल टाइल्स,सेमेटरी, हांडवेयर)	5000 00
47	फुटकर बिजली के सामान के विक्रेता	500.00
48	कपड़ा, थोक विक्रेता	1000 00
49	कैटरिंग	1000.00
50	बेकरी(भट्ठी)	2000.00
51	बेकरी(पॉवर)	1500.00
52	हेयर कटिंग सैलून	300 00
53	ब्यूटी पार्लर	1000 00



54	कुकिंग गैस एजेंसी	1000.00
55	जनरल मर्चेंट थोक	500.00
56	टेलरिंग हाउस (5 से अधिक कर्मचारी)	500.00
57	टेलरिंग हाउस (5 कर्मचारी तक)	300.00
58	कोयला (थोक विक्रेता)	500.00
59	कोयला (फुटकर विक्रेता)	200.00
60	पेंट की दुकान	500.00
61	ज्वैलर्स (बड़े) 5लाख से ऊपर टर्नओवर	2000.00
62	ज्वैलर्स (छोटे) 5लाख तक टर्नओवर	1000.00
63	विज्ञापन एजेंसी	3000.00
64	डैयरी (दूध, पनीर, दही एवं दूध से बनी अन्य पदार्थ)	1000.00
65	भूसा (थोक विक्रेता)	1000.00
66	भूसा (फुटकर विक्रेता)	500.00
67	ऑडियो/विडियो लाइब्रेरी	500.00
68	मोबाइल विक्रेता/विभिन्न मोबाइल कम्पनीयों के रिचार्ज एवं मरम्मत की दुकान	500.00
69	केबिल टी0वी0	1000.00
70	आर्किटेक्ट कंसल्टेन्ट विधि चार्टर्ड एकाउंटेंट फास्ट एकाउंटेंट	2000.00
71	अनाज, तिलहन, चीनी, गुड़, खण्डसारी (थोक विक्रेता)	500.00
72	अनाज, तिलहन, चीनी, गुड़, खण्डसारी (फुटकर विक्रेता)	500.00
73	आईस फैक्ट्री	500.00
74	टेंट हाउस	1000.00
75	हूर पण्ड ड्रैवल्स	2000.00
76	साईबर कैफे (नेट सेवा प्रदाता)	1000.00
77	मसाज केंद्र/आयुर्वेदिक/प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र	2000.00
78	संगीत कला केंद्र	1000.00
दुकान		
79	अंग्रेजी शराब की दुकान	20000.00
80	देशी शराब की दुकान	15000.00
81	पान की दुकान	200.00
82	चाय की दुकान	300.00
83	जनरल मर्चेंट की दुकान (फुटकर)	500.00
84	किताबों की थोक दुकान	500.00
85	किताबों की फुटकर दुकान	200.00
86	न्यूज पेपर	200.00
87	लकड़ी के टाल की दुकान (थोक विक्रेता)	2000.00
88	लकड़ी के टाल की दुकान (फुटकर विक्रेता)	500.00
89	टिम्बर मर्चेंट	5000.00
90	रेडियो/मैकेनिक/टी0वी0 मरम्मत	300.00
91	टी0वी0 शॉप/इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	1000.00

92	फर्टिलाइजर शॉप	1000.00
93	मिठाई की दुकान	1000.00
94	चाट/बताशे की दुकान	1000.00
95	ड्राई फ्रुट विक्रेता (थोक विक्रेता)	1000.00
96	ड्राई फ्रुट विक्रेता (फुटकर विक्रेता)	500.00
97	गैस फिलिंग प्लांट	2000.00
98	सब्जी की दुकान और फल की दुकान	500.00
99	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	1000.00
100	मसाले थोक विक्रेता	1000.00
101	फर्नीचर की दुकान (शील्ड)	1000.00
102	फर्नीचर विक्रेता	1000.00
103	क्रॉकरी विक्रेता	1000.00
104	चूड़ी विक्रेता	500.00
105	मिट्टी के तेल की दुकान	500.00
पशुपालन		
106	प्रति पशु	
	1- कुत्ता	100.00
	2- गाय/भैंस	20.00
	3- अन्य पशु	10.00

### शक्ति

उपरोक्त उपनियम का उल्लंघन नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-29 की उपधारा (1) के अंतर्गत दण्डनीय होगा जो रु0 1000.00 रुपया तक ही हो सकता है। उपनियम का उल्लंघन निरंतर जारी रहने पर अत्यंत जुर्माना लिया जायेगा जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें व्यवसायी द्वारा निरंतर अपराध करते रहना सिद्ध हो जाता है। मूल्य रु0 25.00 प्रतिदिन तक हो सकता है। यह अधिकार, नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार में अंतिम रूप में निहित होगा।

बी0एल0 आर्य,  
अधिशाली अधिकारी,  
नगर पंचायत इमलीखेडा हरिद्वार

विजयनाथ शुक्ल,  
प्रशासक  
नगर पंचायत इमलीखेडा हरिद्वार।

## कार्यालय नगर पंचायत इमलीखेडा जिला हरिद्वार

## विज्ञप्ति

26 अगस्त, 2022 ई०

पत्राक 293 / उपविधि / 2022 -23 उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम-1916) (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश-2002) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश-2007 की धारा-298 (झ) का (घ) एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1986 की धारा-3, 6 व 25 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-1916" के नियम-15(ग), 15(घ) एवं 15(य,घ) तथा उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं धूंकना अधिनियम-2016 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला हरिद्वार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अपने सीमांतर्गत "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि-2022" बनायी गयी है जिसे नगरपालिका अधिनियम-1916 की धारा-301 की उपधारा-1 के अंतर्गत जनसागान्य अथवा जिस पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त हेतु उनसे आपत्तियाँ एवं सुझाव हेतु दैनिक सनाचार पत्र अमर उजाला के अंक 19 जुलाई 2022 में प्रकाशित हुई है, परन्तु इस उपविधि के क्रम में कोई आपत्ति व सुझाव नियत अवधि के अंदर प्राप्त नहीं हुए है।

अतः नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार के प्रशासक महोदय की अनुमति दिनांक 20.08.2022 द्वारा उक्त उपविधि को नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-301 उपनियम-(2) के अंतर्गत उत्तराखण्ड शासकीय गजट में अंतिम प्रकाशन हेतु पुष्टि की गयी है यह उपविधि उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

**"ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि-2022"**

## अध्याय-1

## सामान्य

## 1- संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ-

(क) यह उपविधि नगर पंचायत इमलीखेडा जिला-हरिद्वार "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि-2022" कहलायेगी,

(ख) यह उपविधि उत्तराखण्ड सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

## 2- यह उपविधि नगर पंचायत इमलीखेडा जनपद-हरिद्वार(उत्तराखण्ड) की सीमाओं के भीतर लागू होगी।

## 3- परिभाषाएँ-

किसी विषय या प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उपविधि में निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू रहेंगी-

(क) "बल्क उद्योग और बागवान कचरा" का अर्थ है उद्योगों बागों आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा, जिसमें धारा कतरन खरपतवार कार्बनयुक्त काष्ठ ब्राउन सामग्री जैसे पेड़ों की छँटाई से उत्पन्न कचरा, पेड़ों की कटिंग टहनिया लकड़ी की कतरन, भूस, सुखी पत्तियाँ पेड़ों की छँटाई आदि से उत्पन्न ठोस कचरा, जो दैनिक जैव अपघट्य कचरे के संकलन में समायोजित नहीं किया जा सकता है।

(ख) "बल्क कचरा उत्सर्जन" का अर्थ है कि ठोस अपशिष्ट कचरा प्रबंधन नियम, 2016(जिसे बाद में यहाँ एस०डब्ल्यू०एम० नियम कहा जायेगा) के नियम 3(1)(8) के अंतर्गत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और सम्बद्ध बाह्य कार्यालय के अधिशासी अधिकारी या उससे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक

(ग) "संग्रह" का अर्थ है, ठोस अपशिष्ट उत्सर्जन के स्रोत से ठोस अपशिष्ट को उठाना और संग्रहण बिंदुओं या अन्य स्थान तक पहुँचाना

(घ) "सहाय्य प्राधिकारी" का अर्थ है नगर पंचायत इमलीखेडा जनपद हरिद्वार के अध्यक्ष/प्रशासक एवं अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी/कर्मचारी

(ङ) "निर्माण एवं विध्वंस कचरा" का वही अर्थ होगा, जो निर्माण एवं विध्वंस ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 3(1)(ग) में परिभाषित किया गया है

(च) "स्वच्छ क्षेत्र" का अर्थ है, किसी परिसर के सामने और चारों ओर या निकटवर्ती फुटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल, जिसमें नाली फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल हैं जिनका रख-रखाव इन उपविधियों के अंतर्गत किया जाना है



- (छ) "सामुदायिक कूड़ा घर (बलाब)" का अर्थ है नगरपालिका द्वारा स्थापित और संचालित अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिकों और/ या अधिभोगियों द्वारा मिल कर सड़क किनारे/ऐसे मालिकों/अधिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट के संग्रहण के लिये स्थापित और संचालित कोई संग्रह केंद्र;
- (ज) "कटेनराइज्ड हैब कार्ट" का अर्थ है, ठोस अपशिष्ट के बिंदु दर बिंदु संग्रह हेतु नगर पालिका या उसके द्वारा नियुक्त एजेंसी/एजेंट द्वारा प्रदत्त ठेला
- (झ) "सुपुर्दगी" का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस अपशिष्ट को नगरपालिका के वक्कर या ऐसे ठोस अपशिष्ट की सुपुर्दगी के लिये नगर पंचायत इमलीखेड़ा जनपद हरिद्वार द्वारा नियुक्त प्राधिकृत या लाइसेंस प्रदत्त व्यक्ति को सौंपना अथवा उसे नगर पंचायत या नगर पंचायत द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्रदत्त एजेंसी द्वारा प्रदान किए गये वाहन में डालना।
- (ञ) "ई-कचरा" का अर्थ वही होगा, जो ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2018 के नियम 3(1) (आर) में निर्दिष्ट किया गया है
- (ट) "फिक्सड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस)- का अर्थ है, एक ऊर्जा चालित मशीन जिसका डिजाइन बिखरे हुए ठोस अपशिष्ट को कम्पैक्ट करने के लिए किया गया और प्रचालन के समय स्थिर रहती है। प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाइल भी हो सकती है, जिसे मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस) कहा जा सकता है।
- (ठ) "ठोस अपशिष्ट" का अर्थ है सभी प्रकार का कूड़ा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ शामिल जिसे फैकना अथवा संग्रह करना इन उपविधियों के अंतर्गत प्रतिबंधित है और ऐसा करने से किसी व्यक्ति जीव जंतु को परेशानी होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुँचाने की आशंका हो।
- (ड) "गंदगी फैलाने" का अर्थ है किसी ऐसी बस्ती में गंदगी उत्सर्जित करना, डालना, दबाना अथवा तत्संबंधी अनुमति देना, जहाँ वह गिरती, ढलती, बहती, धुल कर, रिस कर अथवा किसी अन्य तरीके से पहुँचती हो अथवा गंदगी के उत्सर्जित होने बह कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो।
- (ढ) "स्वामि" का अर्थ है जो किसी भवन या भूमि या किसी भाग के मालिक के रूप में अधिकारों का इस्तेमाल करता है
- (ण) "अधिभोगी/पट्टेदार" का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि, भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी/पट्टेदार हो, इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिए किसी भूमि, भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा है।
- (त) "पैलेटाइजेशन" का अर्थ है, एक प्रक्रिया जिसमें पैलेट तैयार की जाती हैं, जो ठोस अपशिष्ट से बने छोटे क्यूब अथवा सिलिंडरीकल टुकड़े होते हैं; और उनके ईंधन पैलेट्स भी शामिल होते हैं जिन्हें रिफ्यूज डेराइव्ड ईंधन कहा जाता है
- (थ) "निर्धारित" का अर्थ है एसडब्ल्यूएम नियमों या इन उपविधियों द्वारा निर्धारित;
- (द) "सार्वजनिक स्थल" का अर्थ है कोई ऐसा स्थान, जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिये सहज सुलभ है, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो या नहीं
- (ध) "संग्रहण" का अर्थ है, ठोस अपशिष्ट को अस्थायी तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गंदगी ना फैले और मच्छर आदि कीटों आकारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोक जा सके;
- (न) "सेनेटरी वर्कर" का अर्थ है, नगर पंचायत के इलाकों में ठोस अपशिष्ट एकत्र करने या हटाने अथवा नलियों को साफ करने के लिये नगर पंचायत/एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति
- (न) "शेड्यूल" का अर्थ है, इन उपविधि से सम्बद्ध शेड्यूल से है
- (प) "इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभारी" का अर्थ है, नगर पंचायत द्वारा समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के जरिए ठोस अपशिष्ट उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क या

प्रभार, ताकि ठोस अपशिष्ट संग्रह, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कवर की जा सके।

- (फ) "खाली प्लेट" का अर्थ है प्राइवेट पार्टी/व्यक्ति/सरकारी एजेंसी से सम्बद्ध कोई ऐसी भूमि या खुला स्थान जिसपर किसी का कब्जा न हो।
- (2) यहाँ प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और लिमिटेड एव विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम-2016 में अभिप्रेत होगा।

## अध्याय-2

### ठोस अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

#### 4- ठोस अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

सभी ठोस अपशिष्ट उत्सर्जकों के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलों से उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ट को नियमित रूप से पृथक् करें और उसे संग्रहित करें। यह पृथक्करण मुख्य रूप से निम्नांकित 3 वर्गों में किया जायेगा-

- (क) गैर-जैव अपघटीय या सूखा कचरा
  - (ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा
  - (ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा और तीनों श्रेणियों के कचरे को कवड कचरा डिब्बों में रखा जाएगा तथा समय-समय पर जारी नगरपालिका के निर्देशों के अनुसार पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं को सौंपेगा।
- i. प्रत्येक बल्क ठोस अपशिष्ट उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट को पृथक् करें और उसे संग्रहित करें निम्नांकित तीन वर्गों में-
- (क) गैर-जैव अपघटीय या शुष्क कचरा
  - (ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा
  - (ग) उपयुक्त कूड़ेदानों में जोखिमपूर्ण ठोस अपशिष्ट, जैविक(गीला) कचरे को अपने परिसर में प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायो गैस आदि तैयार करना एवं पृथक्कृत कचरे को अधिकृत कचरा संग्रहण एजेंसी जरिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केंद्रों या संग्रहण केंद्रों को सौंपेगा और उसके लिए को-भर पंचायत द्वारा समय-समय पर निर्धारित ढुलाई शुल्कों का भुगतान अधिकृत कचरा संग्रह एजेंसी को करेगा।
- iii. पृथक् किए गए ठोस अपशिष्ट के संग्रहण के लिए कूड़ेदानों का रंग इस प्रकार होगा-
- हरा- जैव अपघटीय कचरे के लिए,
- नीला- गैर-जैव अपघटीय या शुष्क कचरे के लिए,
- काला- घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए
- iv. सभी निवासी कल्याण और बाजार संगठन नगर पंचायत के भागीदारी से यह सुनिश्चित करेंगे की उत्सर्जकों द्वारा स्रोत पर कचरे का पृथक्करण किया जाए, पृथक् किए गए ठोस अपशिष्ट को अलग-अलग डिब्बों में संग्रहित किया जाए और फिर से इस्तेमाल करने वाले को सौंपी जाए। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासम्भव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे कचरे को नगर पालिका द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।
- v. 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र कब्जा रखने वाले सभी द्वारबंद समुदाय तथा संस्थान नगर पंचायत की भागीदारी के साथ सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा कचरे का स्रोत पर पृथक्करण हो पृथक् किए गए कचरे को अलग-अलग डिब्बों में रखेंगे और पुन उपयोग आने वाली सामग्री को अधिकृत कूड़ा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुन इस्तेमाल करने वाले को सौंपेगे जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासम्भव परिसर के भीतर ही किया जाएगा इससे बचे हुए ठोस अपशिष्ट को नगर पंचायत द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।
- vi. सभी होटल और रेस्त्रा, नगरपालिका के भागीदारी से, कचरे का स्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक् किए गये ठोस अपशिष्ट को अलग अलग डिब्बे में संग्रहित करेंगे और फिर से

- इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं अथवा अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वालों को सौंपेंगे। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगरपालिका द्वारा निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।
- v. कोई व्यक्ति गैर-लाइसेंसी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हो ऐसा करने के लिये यह जरूरी होगा कि अनुसूची में निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क का भुगतान करते हुए नगर पंचायत को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम लिखित जानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कचरे को स्रोत पर अलग-अलग किया जाए ताकि नगर पंचायत द्वारा निर्धारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौंपा जा सके।
- vi.i सैनेटरी उत्पादों से उत्सर्जित कचरे को तत्सम्बंधी विनिर्माताओं या ब्रांड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पाउचो अथवा अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामग्री में सुरक्षित तरीके से संलेपित किया जाए और उसे गैर-जैव अपघटीय या शुष्क कचरे के लिए बनाये गए कूड़ेदानों में रखा जाना चाहिए।
- ix. प्रत्येक गली विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाद्य सामग्री निपटान योग्य प्लैटे, कप डिब्बे रैपर्स नारियल के छोल बचा खुचा भोजन, सब्जियाँ, फल आदि को अलग-अलग करके उपयुक्त कूड़ेदानों में संग्रहीत करेगा और उसे नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित डिपो या कंटेनर या वाहन को सौंपेगा।
- x. उद्यान और बागवानी के कचरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कचरे को अलग से एकत्र करेंगे और समय-समय पर नगर पंचायत के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान करेंगे।
- xi. घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जाएगा और उसे नगरपालिका या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ऐसे कचरे का संग्रह के लिए साप्ताहिक/समय-समय पर उपलब्ध कराए गए वाहन तक पहुँचाया जाएगा अथवा ऐसे कचरे को उत्तराखण्ड सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कचरा संग्रह केंद्र तक पहुँचाया जाएगा।
- xii. निर्माण कार्यों और भवनों को ढहाए जाने से उत्सर्जित कचरा, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के अनुसार अलग से एकत्र और निपटान किया जाएगा।
- xiii. बायो मेडिकल कचरा ई-कचरा, जोखिमपूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कचरा बिना उपचारित किए ठोस कचरे में मिश्रित नहीं किया जाएगा। ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए तत्सम्बंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा।
- xiv. निर्दिष्ट बूचड़खानों और बाजारों को छोड़ कर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मालिक/कब्जाधारी जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप पोल्ट्री, मछली और पशु वध सम्बंधी कचरा उत्सर्जित करते हो, उन्हें ऐसे कचरे को अलग से बंद कंटेनर में स्वास्थ्य कर स्थिति में एकत्र करना होगा और रोजमर्रा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगरपालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिये प्रदान किए गए कचरा वाहन/स्थल तक पहुँचाना होगा। ऐसे कचरे को सामुदायिक कूड़ा घरों में डालना निषेध होगा।
- xv. पृथक किए गए जैव अपघटीय ठोस कचरे को यदि उत्सर्जक द्वारा कम्पोस्ट न किया गया हो, तो उसे उन्हें अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलिवरी पालिका श्रमिक/वाहन/कचरा एकत्रकर्ता/ कचरा संग्रहकर्ता अथवा ब्लॉक में जैव अपघटीय कचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जकों के लिए प्रदान कराए गए कचरा संग्रह वाहन तक पहुँचाया जाएगा, यह सुपुर्दगी समय-समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी।

### अध्याय-3

#### ठोस अपशिष्ट संग्रह

#### 5- ठोस अपशिष्ट का संग्रह निम्नांकित अनुसार किया जाएगा:-

1. नगर पंचायत के सभी क्षेत्रों या बाड़ों में पृथक किए गए ठोस अपशिष्ट को घर-घर जाकर संग्रह करने के बारे में एसडब्ल्यूएम नियमों का पालन किया जाएगा, जिनके



- अनुसार मलिन और अनौपचारिक बस्तियों सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से कचरा एकत्र किया जाएगा। इसके लिए घर-घर जाकर कचरा एकत्र करने कि अनौपचारिक प्रणाली को नगर पालिका संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।
- ii. प्रत्येक घर से ठोस अपशिष्ट एकत्र करने के लिये क्षेत्रवार विशेष समय निर्धारित किया जाएगा और उसे सम्बद्ध क्षेत्र में खास-खास स्थानों पर प्रचारित किया जाएगा और नगरपालिका वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। घर घर जाकर ठोस अपशिष्ट एकत्र करने का समय सामान्यतः प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया जाएगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकानों या किसी अन्य संस्थागत कचरा उत्सर्जकों से ठोस अपशिष्ट एकत्र करने का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा अथवा नगर पंचायत द्वारा समय-समय पर निर्धारित समय पर होगा।
  - iii. ठोस अपशिष्ट को स्व-स्थाने प्रोसेस करने वाले बल्क कचरा उत्सर्जकों से अविशिष्ट ठोस अपशिष्ट को एकत्र करने के प्रबंध किए जाएंगे।
  - iv. सब्जी फल फूल मांस पोल्ट्री और मछली बाजार से अवशिष्ट ठोस कचरे को रोजमर्रा के आधार पर एकत्र किया जाएगा।
  - v. बागवानी और उद्यान संबंधी ठोस अपशिष्ट अलग से एकत्र किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा इस प्रायोजन के लिये सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जाएंगे।
  - vi. फलों और सब्जी बाजारों, मांस और मछली बाजारों, बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एवं ढुलाई की लागत में कमी लाने के लिए ऐसे ठोस अपशिष्ट को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा, जिसमें वह उत्सर्जित होता है।
  - vii. कंटेनरों में कचरे का हाथ से परिचालन निषेध है। यदि दबावों के कारण अपरिहार्य हो तो ठोस अपशिष्ट का हाथ से निपटान श्रमिकों की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित संरक्षण के तहत किया जाएगा।
  - viii. ठोस अपशिष्ट उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कचरे को नगर पंचायत द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात होपर/ऑटो-टिप्पर/रिक्शा आदि वाहनों में डालने के लिए जिम्मेदार होंगे। बहुमंजिला इमारतों अपार्टमेंटो, आवास परिसरों/इन उपनियमों के खंड 4 व उप-खंड(प) और (अ) के अंतर्गत आने वाले को छोड़कर) से उत्सर्जित पृथक किए गए कचरे को ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा।
  - ix. ठोस अपशिष्ट संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरूरतों और प्रौद्योगिकी में नई खोजों को ध्यान में रखा जाएगा। कचरा एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे ऑटो टिप्पर या वाहन इस्तेमाल किए जाएंगे, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होंगे और उनमें जैव अपघटीय और गैर-जैव अपघटीय कचरे के लिए अलग-अलग दो कंपार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनों पर हूटर भी लगा होगा।
  - x. स्वचालित प्वनि रिकार्डिंग उपकरण, घण्टी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित होंगे भी कचरा संग्रह वाहन में कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।
  - xi. प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा ढुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाएँ और नगरपालिका द्वारा या अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजनाएँ तात्कालिक और जीआईएस मानचित्र में होंगी, जो नगर पंचायत द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित होगी और उनमें प्रारम्भिक बिंदु, प्रारम्भ करने का समय, प्रतीक्षा स्थलों, मार्ग में रुकने का समय, अंतिम बिंदु और निर्दिष्ट मार्ग के अंतिम समय का उल्लेख होगा। नगर पंचायत अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा प्रत्येक गल्ली में एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर प्राथमिक कचरा संग्रह और ढुलाई वाहनों की संरक्ष सारणी प्रदर्शित की जाएगी ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित

- समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सके। ऐसी जानकारी नगर पंचायत की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।
- xii. तंग गलियों में, जहाँ ऑटो टिप्पर या वाहन की सेवाएं संभव न हों, वहाँ एक थ्रीव्हीलर अथवा छोटे मोटरयुक्त वाहन/साइकिल रिकशा काम पर लगाया जायेगा, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हुए कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगा और उसमें गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनों में हूटर लगा होगा और वह मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन के अनुकूल होगा।
- xiii. अत्यंत भीड़ भाड़ वाले और अधिक तंग गलियों वाले क्षेत्रों में जहाँ थ्रीव्हीलर या छोटे वाहन भी न जा सकें वहाँ साइकिल रिकशा अथवा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किए जाएंगे।
- xiv. ऐसी छोटी, तंग और भीड़ी गलियाँ/लेनी में जहाँ थ्रीव्हीलर/रिकशा आदि का संचालन संभव न हो, ऐसे स्थानों पर बस्ती/ गली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी, जहाँ कचरा संग्रह वाहन खड़ा किया जा सके और वाहन के हेल्पर के पास एक सीटी होगी और वे सीटी बजाते हुए गली में ठोस कचरा संग्रहण के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेंगे इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारिणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और नगर पंचायत की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।
- xv. ऑटो टिप्पर, थ्रीव्हीलर्स, रिकशा और सेवा में संलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से कचरा एकत्र करेंगे, और अन्य स्रोतों जैसे बलाव खुले स्थलों, मैदान, कूड़ेदानों और नालियाँ आदि से कचरा एकत्र नहीं करेंगे।
- xvi. नगर पंचायत या उसके अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहता प्राथमिक कचरा संग्रह के लिए क्षेत्र की सभी गलियों/लेनों को कवर करने के लिए जिम्मेदार होगा।

#### अध्याय-4

#### ठोस अपशिष्ट का द्वितीयक संग्रहण

6- द्वितीयक संग्रहण बिंदुओं में ठोस कचरे का संग्रहण निम्नांकित अनुसार किया जाएगा।

- i. घरों में एकत्र किया गया पृथक ठोस कचरा कचरा स्टोरेज डिपो, सामुदायिक कूड़ा घरों या अघल या चल अंतरण स्थलों या कचरे के द्वितीयक संग्रहण के लिए नगर पालिका द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जाएगा।
- ii. ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिंदुओं को कंटेनरों (निर्दिष्ट रंग के) से कवर किया जाएगा, जिन्हें निम्नांकित के लिए अलग-अलग स्टोरेज होगा-
  - (क) गैर-जैव अपघट्य अथवा सूखा कचरा
  - (ख) जैव अपघट्य अथवा गीला कचरा
  - (ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा।
- iii. पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए नगर पंचायत द्वारा चिह्नित अलग-अलग कंटेनरों का इस्तेमाल निम्नांकित अनुसार किया जायेगा-
  - हरा: जैव अपघट्य कचरे के लिए
  - नीला: गैर-जैव अपघट्य कचरे के लिए
  - काला: घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए

नगर पंचायत समय-समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस अपशिष्ट के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित गोदामों की रंग संहिता और अन्य मानदंड अधिसूचित करेगी ताकि कचरे का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव न हो, जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कचरा उत्सर्जकों को करना होगा।

- iv. नगर पंचायत स्वयं अथवा बाहरी एजेंसीयों के जरिये ठोस कचरा संग्रहण केंद्रों का संचालन इस ढंग से करेगी कि उनके आस पास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियाँ पैदा न हो।

- V द्वितीयक संग्रहण डिपुओ में विभिन्न आकार के कंटेनर नगर पंचायत या किन्हीं अन्य निर्दिष्ट एजेंसीयों द्वारा प्रदान किए जाएंगे जो इस उप नियमों में वर्णित अनुसार अलग अलग रंगों के होंगे।
- VI संग्रहण केंद्रों का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रखकर की जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है।
- VII संग्रहण केंद्र इस्तेमालकर्ता अनुकूल होंगे और उनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे कचरा ढका रहे और संग्रहण किए गये कचरे का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पड़े।
- VIII. सभी आवास सहकारी समितियाँ, एसोसिएशनों, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबंद समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उपनियमों द्वारा निर्धारित रंगीन कूड़ेदान रखें और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानों पर पर्याप्त संख्या में ऐसे कंटेनर रखें ताकि वहाँ हर रोज उत्सर्जित कचरा ठीक ढंग से संग्रहीत किया जा सके।
- IX नगर पंचायत या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे साप्ताहिक आधार पर सभी कूड़ाघरों की धुलाई और संरक्षण मुक्त बनाने की व्यवस्था करें।
- X. सूखे कचरे (गैर-जैव अपघटीय कचरा) के लिए रिसाइकलिंग सेंटर-

(क) नगर पंचायत अपने वर्तमान ढलानों अथवा पहचान किए गए खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रिसाइकलिंग केंद्रों के रूप में परिवर्तित करेगा, जिनका इस्तेमाल गलियों/घर-घर जाकर कचरा एकत्र करने सम्बंधी सेवा के जरिए एकत्र किए गए सूखे कचरे को पृथक करने के लिए किया जाएगा। प्राप्त सूखे कचरे की मात्रा के अनुसार रिसाइकलिंग केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

(ख) गली/घर-घर जाकर कचरा संग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा कचरा(गैर-जैव अपघटीय) इन निर्दिष्ट रिसाइकलिंग केंद्रों को स्थानांतरित किया जाएगा ये निर्दिष्ट केंद्र केवल सूखा कचरा प्राप्त करेंगे।

(ग) परिवारों के लिए प्रावधान भी होगा कि वे अपना रिसाइकिल योग्य सूखा कचरा इन रिसाइकलिंग केंद्रों पर सीधे जमा कर सकते हैं अथवा अधिकृत एजेंटों और/ या नगरपालिका से अधिकृत कचरा व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरों के अनुसार बेच सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रिसाइकलिंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत कचरा व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी कि वे रिसाइकिल योग्य कचरे को एसडब्ल्यूएम नियमों के प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक बाजार अथवा रिसाइकलिंग यूनिटों को बेच सकते हैं। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत व्यापारी बिक्री से प्राप्त धनराशि रखने का हकदार होंगे।

#### XI. निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए संग्रहण केंद्र

(क) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के संग्रह के लिए एक संग्रहण केंद्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जायेगा, जहाँ निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्राप्त किया जाएगा, ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यथासम्भव प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा और उसे कचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा।

(ख) नगर पंचायत अपनी एजेंसी को या कुटुम्बही को यह दायित्व सौंप सकती है कि वह सभी कचरा उत्सर्जकों से घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा पृथक्कृत तरीके से एकत्र करें।

(ग) इस तरह प्राप्त किया गया कचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कचरा निपटान केंद्रों पर अलग से लाया जाएगा।

### अध्याय-5

#### छोस अपशिष्ट की कुलाई

7- छोस अपशिष्ट की कुलाई निम्नांकित बातों को ध्यान में रखकर की जाएगी-



- i. ठोस अपशिष्ट की दुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भलीभाँति कवर्ड होंगे ताकि एकत्र कचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पड़े। इन वाहनों में कम्पैक्टर और मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन शामिल हो सकते हैं जो नगरपालिका द्वारा चुनी गयी प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे।
- l. नगर पंचायत द्वारा स्थापित संग्रहण केंद्र कचरे के निपटान के लिए हर रोज काम करेंगे कूड़ेदान या कंटेनरों के आसपास के क्षेत्र को साफ रखा जाएगा।
- li. आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथक्कृत जैव अपघटीय कचरा प्रोसेसिंग प्लांटों जैसे कम्पोस्ट प्लांट, बायो मिथेनेशन प्लांट या अन्य केंद्र तक कवर्ड तरीके से पहुँचाया जाएगा।
- v. जहाँ कहीं प्रयोज्य हो जैव अपघटीय कचरे के लिए, ऐसे कचरे की स्वस्थान प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।
- v. एकत्र किया गया गैर-जैव अपघटीय कचरा सम्बद्ध प्रोसेसिंग केंद्रों अथवा द्वितीयक संग्रहण में पहुँचाया जाएगा।
- vi. निर्माण और विध्वंस जन्य कचरे की दुलाई निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।
- vii. नगर पंचायत कचरे की समुचित ढंग से दुलाई के प्रबंध करेगा। गलियों को बूझाने से उत्पन्न कचरा और गलियों से निकाली गई गाद काम समाप्त होने के तत्काल बाद हटाई जाएगी,
- viii. दुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि अंतिम निपटारे से पहले कचरे के बार-बार परिचालन से बचा जा सके,
- ix. कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाए गए वाहन कचरे को केवल एमटीएस अथवा एफसीटीएस, जहाँ कहीं प्रदान किए गए हों, में जमा/स्थानांतरित करेंगे,
- x. यदि किसी कारणवश एमटीएस/एफसीटीएस निर्दिष्ट स्थल पर खड़े नहीं पाए जाएंगे तो तदा वाहन एमटीएस अथवा एफसीटीएस के अगले निर्दिष्ट स्थल अथवा कचरे को उतारने के लिए नगर पालिका द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा
- x. फिक्सड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन को हूक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा
- xii. कचरे कि दुलाई के दौरान विभिन्न स्रोत से उत्सर्जित कचरे का परस्पर मिश्रण नहीं होना चाहिए।
- xiii. कचरे के गली स्तरीय संग्रहण और दुलाई सेवाएं अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएगी।
- xiv. इस सेवा में सलग्न एमटीएस केवल गली स्तरीय प्रचालनों से कचरा संग्रह करने वाले निर्दिष्ट ऑटो-टिम्पर्स, तिपहिया या अन्य वाहनों/कूड़ेदानों से कचरा प्राप्त करेगा।
- xv. परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर-घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करने में लगे ऑटो-टिम्पर्स, तिपहिया वाहनों, रिक्शा आदि से कचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रूट प्लान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबद्ध एमटीएस तैनात किए जाएंगे।
- xvi. एमटीएस और एफसीटीएस का डिजाइन ऐसा होगा, जो कचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उतारने में कम से कम समय ले और कूड़ा कर्कट इधर-उधर न फैले
- xvi. ठोस कचरे को स्थानांतरित करते समय एमटीएस और एफसीटीएस के इर्दगिर्द रिसे हुए कचरे को साफ किया जाना चाहिए, ताकि कोई रिसाव न बचे। ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद सक्रामण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चाहिए।
- xviii. नगर पंचायत अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेंसी सभी द्वितीयक संग्रहण केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी।

#### अध्याय-6

#### ठोस अपशिष्ट की प्रोसेसिंग

##### 8- ठोस अपशिष्ट की प्रोसेसिंग-

- i. नगर पंचायत ठोस कचरा प्रोसेसिंग केंद्रों और सम्बद्ध ढांचे के निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेंसी के द्वारा इस कार्य को अंजाम देगा ताकि ठोस कचरे के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इसके लिए निम्नांकित

प्रौद्योगिकियों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनायी जाएगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जाएगा-

(क) दुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नवत् रखने के लिए विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी, जैसे बायो- मिथेनेशन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, एनायरोबिक डाइजेशन अथवा जैव अपघटीय कचरे की जैव-स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्धति

(ख) विकेंद्रीकृत स्थलों पर स्थित मध्यम/बड़े कम्पोस्टिंग/बायो मिथेनेशन प्लांटों के जरिए

(ग) कचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के जरिए, ठोस कचरा आधारित बिजली संयंत्रों को कचरे के ज्वलनशील अंश के लिए रिफ्यूज डेराइव्ड ईंधन के रूप में अथवा फीड स्टॉक आपूर्ति के रूप में ईंधन प्रदान करते हुए।

(घ) निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन प्लांटों के जरिए

- i. नगर पंचायत रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल (आरडीएफ) की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा,
- ii. कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भस्मीकरण के लिए कचरे का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्बद्ध अनुबंधों की कार्यशर्तों का हिस्सा होगा।
- iv. नगर पंचायत सुनिश्चित करेगा कि कगज, प्लास्टिक, धातु, कांच, कपड़ा आदि रिसाइकिल योग्य पदार्थ रिसाइकिल करने वाली अधिकृत एजेंसियों को भेजा जाए।

#### 9- ठोस अपशिष्ट की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा-निर्देश-

- i. नगर पंचायत सभी निवासी कल्याण संगठनों समूह आवास समितियों, बाजारों, द्वारबंद समुदायों और 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों सभी होटलों एवं रेस्त्राओं बैंकट हॉल और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासम्भव कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन के जरिए जैव अपघटीय कचरे वाले अन्य कचरा उत्सर्जकों को भी जैव अपघटीय कचरे की स्व-स्थान प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।
- i. नगर पंचायत यह नियम प्रवृत्त करेगा कि सब्जी फल, मांस, पोल्ट्री और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें।
- ii. नगर पंचायत यह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी उद्यानों और पार्कों से उत्सर्जित कचरे का निपटान अलग से यथासम्भव पार्कों और उद्यानों में ही किया जायेगा
- v. नगर पंचायत कचरा प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग, बायो गैस उत्पादन, सामुदायिक स्तर पर कचरे की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा। परंतु ऐसा करते समय बटबू को नियंत्रित रखना और तत्सम्बंधी यूनिट के आस पास स्वच्छता स्थितियां बनाए रखना अनिवार्य होगा।

#### अध्याय-7

##### ठोस अपशिष्ट का निपटान

#### 10- ठोस अपशिष्ट का निपटान

नगर पंचायत ठोस अपशिष्ट और गलियों में झाड़ू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नालियों से निकलने वाली गाद का निपटान एसडब्ल्यूएम नियमों के अंतर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व के अनुरूप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेंसी के जरिए सैनेटरी लैंडफिल और सम्बद्ध बाघे का निर्माण प्रचालन और रख रखाव करेगा।

#### अध्याय-8

इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही ज़ुर्माना/दंड लगाना

#### 11- ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, दुलाई, निपटान के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क:-

- (क) कचरा उत्सर्जकों से कचरा संग्रहण, ढुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिये नगर पंचायत द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इस्तेमालकर्ता शुल्क की दर अनुसूची-1 में निर्दिष्ट है।
- (ख) कचरा उत्सर्जकों से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली नगर पंचायत अथवा नगर पंचायत द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी।
- (ग) नगर पंचायत इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 माह के भीतर इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए कचरा उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगा और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिलिंग/संग्रह/वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा डाटाबेस को नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाएगा।
- (घ) नगर पंचायत ऑनलाइन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्धतियाँ अपनाएगा।
- (ङ) इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी।
- (च) वार्षिक और छमाही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी। यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है तो ऐसे में 12 महीने के बजाए 10 महीने का शुल्क लिया जाएगा। इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि 6 महीने की बजाये साढ़े पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी।
- (छ) अनुसूची-1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 10 प्रतिशत बढ़ जाएगा।
- (ज) इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान/व्यक्ति द्वारा की जाएगी।
- (झ) इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा धूककर्ता से उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये कि भाँती वसूल की जाएगी।

#### 12- एसडब्ल्यूएम नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना/दण्ड-

- (क) एसडब्ल्यूएम नियमों अथवा इन उप-नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप-नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची-2 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।
- (ख) उपरोक्त खंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर-अनुपालन की स्थिति बार-बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महीना जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा।
- (ग) जुर्माना या दण्ड लगाने हेतु निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारी अधिशासी अधिकारी कर निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर, चौकी धाना प्रभारी होंगे तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष के सामान्य या विशेष आदेश के अधीन अन्य अधिकारियों को भी नामित कर सकते हैं। जुर्माना या दण्ड राशि अनुसूची-2 में दी गयी हैं।
- (घ) अनुसूची-2 में वर्णित जुर्माना अथवा दण्ड राशि प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 5 प्रतिशत बढ़ जाएगी।
- (ङ) निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा। जुर्माने का भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशि भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूल की जाएगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

#### अध्याय-9

#### प्रतिभागियों के दायित्व

#### 13- ठोस अपशिष्ट उत्सर्जकों के दायित्व-

##### I. कूड़ा फेंकने पर पाबंदी



- (क) उत्तराखण्ड कूड़ा फैकना एवं शूकना अधिनियम 2016 में दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत किसी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फैलाना अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूड़ेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा नहीं फैलाएगा। कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्रावधान किए गए सार्वजनिक केंद्रों या सुविधाओं को छोड़कर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत बर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने/साफ करने का काम नहीं करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नहीं करेगा।
- (ख) किसी सम्पत्ति पर कूड़ा फैलाना- अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूड़ेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त संपत्ति पर कूड़ा नहीं डालेगा।
- (ग) वाहनों से कूड़ा फैकना- किसी वाहन के ड्राइवर या यात्री के रूप में कोई व्यक्ति किसी गली, सड़क, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा नहीं फैकेगा।
- (घ) मालवाहक वाहन से गंदगी डालना- कोई भी व्यक्ति जब तक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नहीं चलाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया हो ताकि सड़क, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोई लोड, पदार्थ अथवा गंदगी डालने से रोका जा सके।
- (ङ) स्वयं/पालतू पशुओं से गंदगी- कुत्ता, बिल्ली आदि पालतू जानवरों के मालिकों का यह दायित्व होगा कि गली अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवरों द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा/साफ करेगा और इस तरह के उत्सर्जित कचरे के निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटान की वरीयता दी जाएगी।
- (च) नालियों आदि में कचरे का निपटान- कोई व्यक्ति किसी नाली/नदी/खुले ताबाब/जल निकायों में गंदगी नहीं डालेगा।
- ii कचरे को जलाना- सार्वजनिक स्थानों पर या निजी स्थान पर या निषेध सार्वजनिक संपत्ति पर ठोस कचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान निषिद्ध होगा।
- iii. "स्वच्छ क्षेत्र"- प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आस-पास का क्षेत्र स्वच्छ रहे। इन स्थानों में फुटपाथ और खुली नालियां/ गटर सड़क किनारा शामिल हैं, जो किसी भी तरह ठोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए।
- iv सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रदर्शनियां, सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलियां, वाणिज्यिक धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रदर्शनों आदि सहित) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों, जिनमें पुलिस विभाग और/या नगर पंचायत से, अनुमति अपेक्षित हो के मामले में ऐसी गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करें।
- v ऐसे आयोजनों के मामले में आयोजक से नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्ध सफाई निरीक्षक या नगर पंचायत द्वारा अधिकृत कर्मचारी प्राप्त करेगा जो कार्यक्रम की अवधि में उसके पास जमा रहेगी। यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जाच की जाएगी की उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गयी है। यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमें सम्पत्ति को पहुँचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति का हर्जाना नहीं होगा। यदि आयोजनकर्ता, कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरूप उत्सर्जित कचरे की सफाई, संग्रहण और ढुलाई में नगर पंचायत की सेवाएं प्राप्त करना चाहते हो, तो उन्हें नगर पंचायत के सम्बद्ध सफाई निरीक्षक को आवेदन करना होगा तथा इस प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।
- vi. खाली प्लांट पर ठोस कचरा डम्प करने और गैर निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कचरा डाले जाने की स्थितियों से नगर पंचायत निम्नांकित ढंग से निपटेगा-



- (क) नगर पंचायत किसी परिसर के मालिक/अधिभोगी को नोटिस भेज सकता है जिसमें ऐसे मालिक/अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के कचरे को नोटिस में वर्णित तरीके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा।
- (ख) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएँ पूरी करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को समय-समय पर निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा।
- (ग) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगर पंचायत निम्नलिखित कार्यवाही कर सकता है-
- i. ऐसे परिसर में प्रवेश कर कचरे को साफ करना और (पप) अधिभोगी से कचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेगा।
- vii. डिस्पोजेबल उत्पादों और सैनेटरी नेपकिन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्व-
- (क) डिस्पोजेबल उत्पादों जैसे टिन कांच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगर पंचायत के अधिकारी क्षेत्र में आने वाले बाजारों में ऐसे उत्पाद प्रारम्भ करने वाले ब्रैंड मालिकों को कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए नगर पंचायत को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। नगर पंचायत इस प्रावधान के लिए केंद्र सरकार/राज्य सरकार के सम्बद्ध विभागों के साथ समन्वय कर सकती है।
- (ख) ऐसे सभी ब्रैंड मालिकों को, जो गैर-जैव अपघट्य पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं, उन्हें ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कचरे को वापस लिया जा सके।
- (ग) सैनेटरी नेपकिन और डायपर्स विनिर्माता या ब्रैंड मालिक या विपणन कंपनियां इस बात की संभावनाओं का पता लगाएंगी कि उनके उत्पादों में सभी रिसाइकिल योग्य पदार्थों का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है अथवा वे अपने सैनेटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी, जिनसे नेपकिन या डायपर का निपटारा किया जा सके।
- (घ) ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रैंड मालिक या विपणन कंपनियां अपने उत्पादों की रैपिंग और डिस्पोजल के लिए लोगों को शिक्षित करेंगी।

#### 14- नगर पंचायत के दायित्व-

- i. नगर पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भू-भाग में सभी साइड गलियाँ/मार्ग, सार्वजनिक स्थलों अस्थाई बस्तियाँ, मस्जिद क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों बागों, नालियाँ आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी, वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीनें लगाएंगी तथा घोषित संग्रहण कंटेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुँचाने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए नगर पालिका अपने सफाई स्टाफ और वाहनों के अलावा अनुबंध के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को काम पर लगा सकता है, अथवा सरकारी निजी भागीदारी व्यवस्था का सहारा ले सकता है। इसके अतिरिक्त नगर पालिका सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों ऐसे वाणिज्यिक क्षेत्रों की पहचान करेगा, जिनमें दिन में दो बार झाड़ू लगाने की आवश्यकता हो।
- ii. नगर पंचायत अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गों, रेलवे स्टेशनों बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रों आदि के आसपास पर्याप्त सड़क में और पर्याप्त आकार के कूड़ेदानों का रख रखाव करेगा।
- i. नगर पंचायत विकेंद्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ट करेगा, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय अथवा सार्वजनिक स्थलों पर बने पेशाबघरों, सार्वजनिक कचरे के लिए बनाए ट्रांसफर स्टेशन लैंडफिल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थानों की निगरानी रख सके।
- v. सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के पृथक्करण संग्रह, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान कार्यों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त सड़क में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जिससे कम से कम अधिशासी अधिकारी रैंक के अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी।

- v. प्रत्येक वाडे निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरूप कार्मिक तैनाती किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती सुक्तिसंगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी। नगर पंचायत जहाँ कहीं अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असमर्थ होगा, तो वह अनुबध के जरिए बाहरी एजेंसीयो से यह काम करा सकती है। प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
- vi. नगर पंचायत अद्यतन सड़क/गली क्लिनिंग मशीनों, मैकेनिकल स्वीपरो अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करेगा जिनसे झाड़ू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा।
- vii. नगर पंचायत सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान के माध्यम से जागरूकता और सवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जकों और अन्य हितभोगियों को एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित करेगा, जिसमें इस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना/दंड सम्बंधी प्रावधानों की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा।
- viii. नगर पंचायत कचरा उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले कचरे का स्वोत् पर ही उपचार करें। नगर पंचायत विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों जैसे बायो मिथेनेशन, कम्पोस्टिंग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है। इन प्रोत्साहनों में परिवारी, निवासी कल्याण संगठनों और संस्थानों आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रदान करना उनके नाम सम्बद्ध वेबसाइटों में प्रकाशित करना अथवा सम्पत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते हैं।
- ix. नगर पंचायत स्वयं द्वारा रख रखाव किए जा रहे सभी पाकों उद्यानों और जहाँ कहीं संभव हो अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर घरणबद्ध तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उसमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा। अनौपचारिक कचरा रिसाइकलिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रिसाइकलिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते हैं।
- x. नगर पंचायत ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचारु और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हें ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सके।
- xi. नगर पंचायत यह सूचित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी, फ्लोरेसंट जैकेट दस्ताने रैनकोट समुचित फुटवेयर और मास्क प्रदान किए जाए, जो ठोस कचरा परिचालन कार्य करते हैं और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए।
- xii. नगर पंचायत कचरे के संग्रहण, परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा।
- xiii. किसी ठोस कचरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केंद्र अथवा लैंडफिल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल नगर पंचायत को रिपोर्ट करेगा, जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केंद्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।
- xiv. नियमित जांच-अध्यक्ष/प्रशासक अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वाई के विभिन्न भागों और ठोस कचरे के संग्रहण, ढुलाई प्रोसेसिंग और निपटान से संबंधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन हो रहा है।
- xv. नगर पंचायत अपने मुख्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेगा। इस पीजीआरएस में एसएमएस आधारित सेवा, मोबाइल ऐप्लीकेशन अथवा वेब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती हैं।
- xvi. नगर पंचायत एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के कार्यान्वयन से सम्बद्ध कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए कार्ड प्रौद्योगिकियों/आईसीटी प्रणाली कायम करेगा तथा ऐसी प्रणाली को वेतन/विहाडी/परिश्रमिक के साथ एकीकृत करने का प्रयास करेगा।



- xvii. पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुँच- अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए नगर पंचायत अपनी वेबसाइट से सारी आवश्यक सूचनाएँ प्रदान करेगा।
- xviii. नगर पंचायत एसडब्ल्यूएम नियमों में वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगा, जो इन उपनियमों में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं किए गए हैं।

## अध्याय-10

## विविध

- 15- इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे अध्यक्ष/प्रशासक, नगर पंचायत के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामलों में अंतिम होगा।
- 16- सरकारी निकायों के साथ समन्वय- नगर पंचायत अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों के अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण में आने वाले इलाकों सुनिश्चित किया जा सके। कोई कठिनाई होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।
- 17- सक्षम प्राधिकारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और इन उपविधियों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं।

## अनुसूची-1

## ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क

1	2	3
क्र० सं०	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/ अपशिष्ट का प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (यूजर चार्ज रुपये में)
1	गरीबी रेखा से नीचे के घर(बी.पी.एल कार्ड धारक)	₹ 30.00 प्रतिमाह
2	गरीबी रेखा से ऊपर एवं मध्यम आय वर्ग के व्यक्ति/परिवार	₹ 50.00 प्रतिमाह
3	उच्च वर्ग के परिवार/मकान	₹ 100.00 प्रतिमाह
4	सब्जी एवं फल विक्रेता	₹ 10.00 प्रतिदिन ठेली पर केरी ₹ 50.00 प्रतिमाह दुकान एवं पड
5	भाँस एवं माछली विक्रेता	₹ 500.00 प्रतिमाह
6	रेस्टोरेंट	₹ 100.00 प्रतिमाह छोटे रेस्टोरेंट ₹ 500.00 प्रतिमाह मध्य रेस्टोरेंट ₹ 1000.00 प्रतिमाह बड़े रेस्टोरेंट
7	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाउस	₹ 200.00 प्रतिमाह 20 बेड तक ₹ 500.00 प्रतिमाह 21 बेड से 40 बेड तक ₹ 1000.00 प्रतिमाह 41 बेड से 100 बेड तक तथा इससे अधिक पर प्रति बेड ₹ 10 अतिरिक्त
8	धर्मशाला	₹ 500.00 प्रति उत्सव/समारोह
9	बारातघर (चेरिटेबल)	₹ 500.00 प्रति उत्सव/समारोह
	बारातघर (नॉन-चेरिटेबल)	₹ 2000.00 प्रति उत्सव/समारोह
10	बेकारी	₹ 200.00 प्रतिमाह
11	कार्यालय/बैंक	₹ 200.00 प्रतिमाह 50 कर्मचारी तक ₹ 500.00 प्रतिमाह 51 से 100 कर्मचारी तक ₹ 800.00 प्रतिमाह 101 से अधिक कर्मचारी तक
12	स्कूल/शिक्षण संस्थाएँ (आवासीय)	₹ 2000.00 प्रतिमाह 50 बेड तक और उससे अधिक पर ₹ 10.00 प्रति बेड
13	स्कूल/शिक्षण संस्थाएँ (अनावासीय)	₹ 1000.00 प्रतिमाह 500 विद्यार्थियों तक ₹ 5000.00 प्रतिमाह 501 से अधिक विद्यार्थियों तक

14	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बायोमेट्रिकल वेस्ट को छोड़कर)	₹ 500.00 प्रतिमाह 20 बेड तक
		₹ 1000.00 प्रतिमाह 21 से 40 बेड तक
		₹ 2000.00 प्रतिमाह 41 से 100 बेड तक
		₹ 5000.00 प्रतिमाह 101 से अधिक बेड तक
15	क्लीनिक/ पैथोलोजी	₹ 100.00 प्रतिमाह क्लीनिक
		₹ 300.00 प्रतिमाह पैथोलोजी
16	दुकान/चाय की दुकान	₹ 100.00 प्रतिमाह छोटी दुकान
		₹ 200.00 प्रतिमाह बड़ी दुकान
17	फैक्ट्री	₹ 500.00 प्रतिमाह छोटी
		₹ 1000.00 प्रतिमाह बड़ी
18	वर्कशॉप	₹ 200.00 प्रतिमाह छोटा वर्कशॉप
		₹ 500.00 प्रतिमाह बड़ा वर्कशॉप
19	कबाड़ी	₹ 200.00 प्रतिमाह छोटा कबाड़ी
		₹ 500.00 प्रतिमाह बड़ा कबाड़ी
20	जूस/गन्ने का रस विक्रेता	₹ 10.00 प्रतिदिन ठेली/फंड
		₹ 500.00 प्रतिमाह दुकान
21	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन जिनमें अपशिष्ट उत्पन्न हो।	₹ 500.00 प्रतिदिन होटल
		₹ 1000.00 प्रतिदिन बैंडिंग पॉइंट
		₹ 2000.00 प्रतिदिन सार्वजनिक/निजी स्थल पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन
22	ठहान तथा निर्माण सम्बंधी अपशिष्ट	₹ 200.00 प्रतिदिन 0.50 घनमीटर तक
		₹ 500.00 प्रतिदिन 1.00 घनमीटर तक
		₹ 1000.00 प्रतिदिन 6.00 घनमीटर तक तथा उससे अधिक पर ₹ 200.00 घनमीटर अतिरिक्त
23	सिनेमा हॉल	₹ 500.00 प्रतिमाह
24	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य(प्रतिष्ठान की स्थिति के अनुसार)	₹ 500.00 बड़ी दुकान अथवा टुपलैक्स दुकान
		₹ 1000.00 शॉरूम/काम्पलेक्स/टावर

इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार का भुगतान मांग जारी होने से 30 दिन के भीतर न किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से विलंब भुगतान/प्रभार (एलपीएससी) लगाया जाएगा।

## अनुसूची-2

## जुर्माना/दंड

क्र० सं०	नियम/उप नियम संख्या	अपराध	निम्नांकित पर लागू	प्रत्येक घूक के लिए जुर्माना (रुपये में)
1.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(क)	कचरे को पृथक् करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार साँपने में विफल रहना।	आवासीय ब्लक जनरेटर	200.00
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह/पार्टी हॉल, फेस्टिवल हॉल, पार्टी लॉन, प्रदर्शनी और मेले स्थल	500.00
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लब्स, सिनेमाघरों, पब्स, सामुदायिक हॉल, मल्टीप्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थान	5000.00
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर-आवासीय स्थान	2000.00



			फिस, मोट विक्रेता द्वारा कूड़े को पृथक्करण तरीके से न रखना	200.00
	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2)	सड़क/गली में 1.कूड़ा फैकना, थूकना  2.नहाना, पेशाब करना,जानवरों को धारा खिलाना, कपड़े धोना, वाहन धोना, गोबर नाली में बहाना	उल्लंघनकर्ता	200 से 500 एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूड़ा फैकना, एवं थूकना प्रति प्रतिशोध अधिनियम 2016 के अंतर्गत होगी। 500.00
2.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1) (ख)और (घ)	नियमानुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने में विफल रहना। नियम के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय  गैर-आवासीय/बल्क जनरेटर	200.00  500.00
3.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ग)	नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय  गैर-आवासीय/बल्क जनरेटर	500.00  2000.00
4.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(ट)	ठोस कचरे को खुले में जलाना	उल्लंघनकर्ता	2000.00
5.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(4).	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना	ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर - से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेंट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो	5000.00
6.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(5).	नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता/वैडर कूड़ादान न रखने एवं कूड़े को पृथक्करण न करने, अपशिष्ट अप्पड़ारन डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहने पर	उल्लंघनकर्ता	200.00
7.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(छ)	सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, गलियों आदि में गंदगी फैलाना/कुत्ते/अन्य जानवरों द्वारा मल त्याग/उत्सर्जित कचरे के निपटान में विफलता	अपराधी	500.00
निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा।				

8.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(5),	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	निवासी कल्याण एसोसिएशन, आर.डब्ल्यू.ए	5000.00
			बाजार एसोसिएशन, संघ	10,000.00
9.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(7),	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	द्वारबंद समुदाय	5000.00
			संस्थान	10,000.00
10.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(8),	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	होटल	10,000.00
			रेस्टोरेंट	5000.00
11.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(2), *	उत्पादन के कारण सृजित पैकेजिंग कचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किये बिना डिस्पोजल उत्पादों की बिक्री अथवा विपणन	विनिर्माता और/या ब्रॉड ऑनर/स्वामी	50,000.00
12.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(3)	नियमों के अनुसार उपाय करने में विफलता	विनिर्माता और ब्रॉड स्वामी और विपणन कम्पनियां	25,000.00
13.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 15(ड)	नियमों के उपाय करने, भवन योजना में अपशिष्ट संग्रहण केंद्र स्थापित करने में विफलता	उत्संघनकर्ता, शुप हाउसिंग सोसाइटी या मार्केट कॉम्प्लेक्स आदि	25,000.00
14.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(ग)	गलियों, पहाड़ियों, सार्वजनिक स्थलों में अपशिष्ट यथा कागज, पानी की बोतल, शराब की बोतल, सॉफ्ट ड्रिंक, कैन टैट्रा पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट को फेंकने पर	उत्संघनकर्ता/पर्यटक/वाहन/ धालक	500.00
15.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(घ)	नगरपालिका की उपविधि को होटल/अपशिष्टगृह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने में विफलता	उत्संघनकर्ता/होटल/अतिथि गृह स्वामी	500.00
16.		सार्वजनिक सभाओं(जुलूस प्रदर्शनियों, सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलियां, वाणिज्यिक, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रदर्शन आदि सहित से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित गतिविधियों के क्षेत्र एवं आस-पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने में विफलता)	आयोजनकर्ता	2000.00

बी०एल० आर्य,

अधिकांशी अधिकारी,

नगर पंचायत इमलीखेडा, हरिद्वार।

विजयनाथ शुक्ल,

प्रशासक,

नगर पंचायत इमलीखेडा, हरिद्वार।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 48 हिन्दी गजट/682-भाग 8-2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।